वर्ष 12 • अंक 258 • 14 पृष्ठ • मूल्य 5 रुपये

मंगलवार 17 दिसंबर 2019

कोलकाता, चंडीगढ़, **नई दिल्ली**, पटना, भोपाल, मुंबई, रायपुर और लखनऊ से प्रकाशित।

भारत का पहला संपूर्ण हिंदी आर्थिक अखबार

बिज़नेस स्टैंडर्ड

www.bshindi.com

पृष्ठ 6

प्याज के दाम में फिर आई उछाल

लक्ष्मी निवास मित्तल ▸▸ पृष्ठ 3

आर्सेलर-निप्पॉन ने पूरा किया एस्सार का अधिग्रहण

डॉलर रु. 71.00 ▲ 20 पैसे | यूरो रु. 79.10 ▼ 10 पैसे | सोना (10ग्राम) रु 37882 ▲ 206 रुपये | सेंसेक्स 40938.70 ▼ 71.00 | निफ्टी 12054.00 ▼ 32.80 | निफ्टी फ्यूचर्स 12082.60 ▲ 28.60 | ब्रेंट क्रूड 67.10 डॉलर ▲ 0.20 डॉलर

एक नज़र

थोक मुद्रास्फीति नवंबर में 0.58 प्रतिशत पर

खाद्य वस्तुओं की कीमतों में तेजी से थोक मूल्य आधारित महंगाई दर नवबंर में बढ़कर 0.58 प्रतिशत हो गई। अक्टूबर में यह 0.16 प्रतिशत पर थी। मासिक थोक मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई नवंबर 2018 में 4.47 प्रतिशत दर्ज हुई थी। सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार खाने-पीने के सामान की महंगाई अक्टूबर में 9.80 प्रतिशत से बढ़कर नवंबर 2019 के दौरान 11 प्रतिशत पर पहुंच गई। गैर-खाद्य उत्पाद में महंगाई अक्टूबर में 2.35 प्रतिशत से कम होकर नवंबर में 1.93 प्रतिशत रह गई। पृष्ठ 4

जियो के टावर ब्रुकफील्ड को बेचेगी रिलायंस

रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सोमवार को कहा कि वह जियो की दूरसंचार टावर परिसंपत्तियां कनाडा की ब्रुकफील्ड फील्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर पार्टनर्स एलपी को 25,215 करोड़ रुपये में बेचेगी। आरआईएल ने कहा कि उसकी इकाई रिलायंस इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स ऐंड होल्डिंग्स लिमिटेड (आरआईआईएचएल) ने ब्रुकफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर्स और उसके साझेदारों के साथ टावर कारोबार सौदे के लिए बाध्यकारी समझौता किया है। ब्रुकफील्ड टावर कंपनी की 100 प्रतिशत इक्विटी हिस्सेदारी खरीदेगी। इस सौदे के तहत टावर इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट की प्रायोजक आरआईआईएचएल ब्रुकफील्ड से संबद्ध बीआईएफ-चार जारविस इंडिया और कुछ अन्य सह निवेशकों के लिए ट्रस्ट में शेयर जारी करेगी। पृष्ठ 2

चौबीसों घंटे मुफ्त एनईएफटी की सुविधा शुरू

अब देश में एनईएफटी सुविधा के जरिये धन के अंतरण पर किसी तरह का शुल्क नहीं देना होगा। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कहा कि बैंक बचत खाता धारकों से ऑनलाइन या मोबाइल बैंकिंग के जरिये एनईएफटी पर किसी तरह का शुल्क नहीं लेंगे और यह सुविधा सप्ताह में सातों दिन 24 घंटे उपलब्ध होगी। आरबीआई ने कहा कि चौबीसों घंटे एनईएफटी की सुविधा के साथ भारत गिने-चुने देशों के शीर्ष क्लब में शुमार हो गया है।

अनिल अंबानी के खिलाफ दावा खारिज

ब्रिटेन के उच्च न्यायालय ने रिलायंस कम्युनिकेशंस के चेयरमैन अनिल अंबानी के खिलाफ चीन के बैंकों का दावा खारिज कर दिया है। अंबानी के एक प्रवक्ता ने सोमवार को कहा कि चीन के बैंकों ने 68 करोड़ डॉलर का दावा किया था, जिसे ब्रिटेन के न्यायालय ने स्वीकार नहीं किया। प्रवक्ता ने कहा कि इस मामले पर 7 नवंबर को सुनवाई शुरू हुई थी और इस पर आदेश सोमवार को आया। अंबानी के खिलाफ दायर याचिका में चीन के बैंकों ने आरकॉम को अपने निगमित ऋणों के एवज में 68 करोड़ डॉलर का दावा ठोका था।

यामाहा ने वापस मंगाईं 7,757 मोटरसाइकिलें

इंडिया यामाहा मोटर ने एफजेड एफआई और एफजेड-एस एफआई मॉडल की 7,757 मोटरसाकिलों को बाजार से वापस मंगाया है। इन बाइक के रियर साइड रिफ्लेक्टर में खराबी है जिसे दुरुस्त करने के लिए कंपनी ने इन्हें वापस मंगाया है। कंपनी ने बयान कहा कि इन मोटरसाइकिलों का विनिर्माण अक्टूबर, 2019 से हुआ है। कंपनी ने कहा कि इन वाहनों के रिफ्लेक्टर को यामाहा के अधिकृत डीलरों पर नि:शुल्क फिट कराया जा सकता है। इस बारे में बाइक मालिकों से कंपनी खुद संपर्क करेगी।

बैंकों में फिर पूंजी डालेगी सरकार!

विलय के बाद सार्वजनिक बैंकों में पुनर्पूंजीकरण पर हो सकता है निर्णय

हंसिनी कार्तिक
मुंबई, 16 दिसंबर

- बजट में वित्त मंत्री कर सकती हैं इसके लिए प्रावधान
- विलय से संबंधित प्रक्रिया अभी चल रही है
- कितनी पूंजी की होगी जरूरत, उसका किया जा रहा है आकलन
- विलय के कारण अतिरिक्त प्रावधान से बढ़ सकता है एंकर बैंकों पर बोझ
- अगले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में मिल सकती है पूंजी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा इस साल सितंबर में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के एकीकरण की घोषणा के करीब तीन माह बाद इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए इसमें शामिल 10 बैंक आकलन के अग्रिम चरण में हैं। पंजाब नैशनल बैंक (पीएनबी), यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक और इंडियन बैंक को एंकर बैंक माना गया है, जो अपेक्षाकृत 6 छोटे बैंकों का अपने में विलय करेंगे।

विलय से बैंकों पर अतिरिक्त प्रावधान का बोझ आएगा, ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि आगामी आम बजट में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी डालने के एक और चरण की शुरुआत हो सकती है। बैंकों को कितनी मात्रा में पूंजी की जरूरत होगी और सरकार इसमें कितनी पूंजी का योगदान कर सकती है, इस बारे में जांच-परख की प्रक्रिया जोर-शोर से की जा रही है। केनरा बैंक ने ऑडिट और कंसल्टेंसी फर्म पीडब्ल्यूसी को नियुक्त किया है, वहीं इंडियन बैंक ने केपीएमजी को नियुक्त किया है। डेलॉयट को पीएनबी और यूनियन बैंक से इस काम का जिम्मा मिला है।

इंडियन बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्याधिकारी पद्मजा चुंदरू ने कहा, 'हमें उम्मीद है कि जांच-परख की प्रक्रिया दिसंबर तक पूरी हो जाएगी।' सार्वजनिक क्षेत्र के एक बैंक के शीर्ष कार्याधिकारी के अनुसार विलय की प्रक्रिया चल रही है, वहीं एकीकरण में शामिल सभी बैंकों से जांख-परख का काम 31 दिसंबर तक पूरा करने को कहा गया है। उन्होंने कहा, 'जनवरी 2020 की पहले या दूसरे हफ्ते में इस जांच-परख के नतीजे सामने आने की उम्मीद है और यह भी पता चल जाएगा कि एंकर बैंकों को कितना अतिरिक्त प्रावधान करना पड़ेगा और विलय की वजह से बैंकों को अपने खाते में उसे शामिल करना होगा।'

बैंकर वित्त वर्ष 2020 की दिसंबर और मार्च तिमाही के वित्तीय नतीजों में विलय से संबंधित प्रावधान की लागत को दिखा सकते हैं। एक अन्य बैंकर ने कहा, 'अगली दो तिमाहियों में बैंक एक बार फिर घाटे में जा सकते हैं। हमारा मानना है कि पूंजी पर्याप्तता की समस्या नहीं होगी क्योंकि बैंक में पूंजी डालने की प्रक्रिया हाल ही में पूरी हुई है।'

हालांकि एकीकरण पूरा होने के बाद पूंजी डालने की प्रक्रिया एक बार फिर शुरू होने की उम्मीद है। एकीकरण प्रक्रिया में शामिल एक अन्य सार्वजनिक बैंक के प्रमुख ने कहा, 'एकीकृत इकाई 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगी और हमारा मानना है कि एकीकृत बैंकों में पूंजी निवेश अगले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में हो सकती है।'

आम बजट में कितनी राशि के पुनर्पूंजीकरण की घोषणा की जा सकती है, उसका अनुमान लगाना अभी जल्दबाजी होगा। लेकिन बैंकरों का कहना है कि शायद यह पिछले चरण जितना बड़ा नहीं होगा। खातों को दुरुस्त करने और नियामकीय पूंजी सीमा को बरकरार रखने के लिए वित्त वर्ष 2018 से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में करीब 2.66 लाख करोड़ रुपये की पूंजी डाली जा चुकी है। इस बार केनरा बैंक, पीएनबी और यूनियन बैंक में एस्सार स्टील के समाधान से करीब 8,857 करोड़ रुपये मिल रहे हैं। ऐसे में पुनर्पूंजीकरण की राशि 50,000 करोड़ रुपये या इससे कम हो सकती है।

एक बैंकर ने कहा, 'बैंकों के विलय पर काम करने में हमारे लिए कठिनाई अतिरिक्त प्रावधान का आकलन करने में हो रही है क्योंकि ऋण खाते पर अंतर-ऋणदाता समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं। हमें उम्मीद है कि इनमें से 50 मामलों का समाधान हो सकता है लेकिन इस बारे में निश्चित तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता।'

राज्यों को 35,000 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति जारी

इंदिवजल धस्माना
नई दिल्ली, 16 दिसंबर

जीएसटी मामला

- बुधवार को जीएसटी परिषद की बैठक से पहले राज्यों का असंतोष दूर करने की कोशिश
- कई राज्य जीएसटी मुआवजा मिलने में देरी से नाखुश

केंद्र ने बुधवार को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की बैठक से पहले आज राज्यों को अपने पाले में करने की कोशिश की। राज्यों का असंतोष दूर करने के लिए केंद्र ने राज्यों को बकाया रकम के एवज में 35,000 करोड़ रुपये निर्गत किए हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने एक ट्वीट में कहा, 'केंद्र सरकार ने जीएसटी मुआवजे के तौर पर राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को 35,198 करोड़ रुपये जारी किए हैं।'

समझा जा रहा है कि बुधवार को जीएसटी परिषद की बैठक से पहले इससे राज्यों के बीच सकारात्मक संदेश जाएगा। प्रस्तावित बैठक में राज्यों को बकाया रकम देने के लिए धन जुटाने के विभिन्न उपायों पर चर्चा की जा सकती है। राज्य सभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बयान के अनुसार केंद्र राज्यों को मुआवजे के रूप में 9,783 करोड़ रुपये का भुगतान कर चुका है। सीतारमण के अनुसार यह उपकर से जुटाई गई रकम से अधिक है।

उन्होंने कहा कि इस वर्ष 31 दिसंबर तक 55,467 करोड़ रुपये जुटाए गए थे, लेकिन राज्यों को 65,250 करोड़ रुपये भुगतान किया गया था। पिछले सप्ताह भाजपा शासित राज्य भी मुआवजा उपकर मुद्दे पर वित्त मंत्री के जवाब पर सकते में आ गए थे। वित्त मंत्री ने संसद के ऊपरी सदन में कहा था कि सरकार ने 2019-20 में अक्टूबर अंत तक बतौर उपकर जितनी रकम जुटाई थी, उससे अधिक वह राज्यों को जारी कर चुकी है। वित्त मंत्री के जवाब में भाजपा शासित राज्य के वित्त मंत्री ने कहा, 'आखिर यह कैसे संभव है? पिछले दो वर्षों के उपकर अधिशेष कहां हैं? क्या वित्त मंत्री यह कहना चाहती हैं कि केंद्र ने संचित निधि से इस रकम का भुगतान किया है?'

मुआवजा अधिनियम के तहत अगर राज्यों का जीएसटी से प्राप्त राजस्व आधार वर्ष 2015-16 पर कम से कम 15 प्रतिशत रफ्तार से नहीं बढ़ता है तो केंद्र प्रत्येक दो महीने में इस अंतर का भुगतान करता है। इससे पहले राज्य खफा चल रहे थे, क्योंकि जीएसटी बैठक के लिए प्रस्तावित आधिकारिक मुद्दों में मुआवजा उपकर भुगतान हिस्सा नहीं है। इस महीने के शुरू में गैर-भाजपा शासित राज्यों के वित्त मंत्रियों ने सीतारमण से मुलाकात की थी और जीएसटी मुआवजे के भुगतान में विलंब पर चिंता जताई थी। इनमें ज्यादातर राज्यों की यह शिकातय थी कि मुआवजे में देरी से उनकी वित्तीय स्थिति प्रभावित हो रही है, जिसका सीधा असर विकास कार्यों पर हो रहा है। जीएसटी परिषद की बैठक में कर आधार बढ़ाने, अतिरिक्त संसाधन जुटाने और कर अनुपालन बढ़ाने के लिए राजस्व संवर्द्धन समिति एक प्रस्तुति पेश करेगी।

पतंजलि के कर्ज पर बैंक राजी

देव चटर्जी
मुंबई, 16 दिसंबर

- रुचि सोया के अधिग्रहण के लिए बैंकों से मिलेगा कर्ज
- इससे पहले बैंकों ने कर्ज पर नहीं दी थी सहमति
- रुचि सोया समाधान मामले में बैंकों को 65 फीसदी उठाना पड़ेगा नुकसान

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने पतंजलि आयुर्वेद को रुचि सोया के अधिग्रहण के लिए 4,000 करोड़ रुपये का कर्ज देने का निर्णय किया है। रुचि सोया ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता के तहत दिवालिया प्रक्रिया का सामना कर रही है। इससे पहले बैंकों की ओर से ऋण देने पर सहमति नहीं जताई गई थी, जिससे रुचि सोया के सौदे को लेकर संशय बना हुआ था।

बैंकों द्वारा कर्ज देने पर सहमत होने से सरकारी बैंकों को रुचि सोया में अपने पहले के निवेश पर 65 फीसदी नुकसान के साथ समाधान करने में मदद मिलेगी। एसबीआई के नेतृत्व में बैंकों ने कर्ज का भुगतान नहीं करने पर रुचि सोया पर 12,146 करोड़ रुपये का दावा किया था। पतंजलि समूह के प्रवक्ता से इस बारे में पक्ष जानने के लिए संपर्क नहीं हो पाया। केयर रेटिंग्स द्वारा अक्टूबर में पतंजलि की रेटिंग वापस लिए जाने के बाद बैंकों की ओर से कंपनी को यह कर्ज दिया जा रहा है। 24 अक्टूबर को केयर ने कंपनी की रेटिंग 'केयर ए-' को वापस ले लिया था। 17 अक्टूबर को केयर ने 4,350 करोड़ रुपये में रुचि सोया के अधिग्रहण को देखते हुए कंपनी की रेटिंग 'वॉच और बढ़ती जटिलताएं' कर दी थी क्योंकि यह मार्च 2019 में पतंजलि आयुर्वेद की कुल हैसियत का 151 फीसदी था। इससे पहले उसकी रेटिंग दो पायदान घटाकर केयर ए- कर दिया था।

पतंजलि आयुर्वेद पतंजलि समूह की सबसे बड़ी कारोबारी इकाई है। ऐसे में रुचि सोया के भारी भरकम अधिग्रहण का ज्यादा भार इसी कंपनी को वहन करना होगा। इसके साथ ही एफएमसीजी, हर्बल और आयुर्वेदिक उत्पादों को लेकर बढ़ती प्रतिस्पर्द्धा भी कंपनी के लिए चिंता का विषय है। कंपनी ने कहा कि रुचि सोया के अधिग्रहण के लिए 900 करोड़ रुपये का वित्त पोषण विशेष उद्देश्यीय कंपनी के जरिये निवेश किया जाएगा लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो पाया है।

अदालत ने आईटीसी बंदिश पर मांगा जवाब

बीएस संवाददाता
नई दिल्ली, 16 दिसंबर

- पूरा इनवॉयस नहीं होने से बड़े कारोबारियों का फंस रहा पैसा
- छोटे कारोबारियों से माल खरीदने से परहेज कर सकते हैं बड़े कारोबारी

दिल्ली उच्च न्यायालय ने इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के दावे पर लगी बंदिशों पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। केंद्र सरकार ने 11 नवंबर को एक सर्कुलर जारी कर मिसिंग इनवॉइस के एवज में पात्र क्रेडिट का 20 फीसदी ही दावा करने का नियम बना दिया था। इससे बड़े कारोबारी को छोटे कारोबारी से खरीद करने पर उनकी आईटीसी की राशि तीन महीने तक फंस रही है।

दिल्ली उच्च न्यायालय में इस सर्कुलर और सीजीएसटी नियम 36 (4) को चुनौती दी गई है, जिस पर उच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। बड़े कारोबारी मासिक और छोटे कारोबारी तिमाही आधार पर रिटर्न भरते हैं। ऐसे में बड़े कारोबारी द्वारा आईटीसी दावे के समय छोटे कारोबारी के सभी इनवॉइस उपलब्ध नहीं होते हैं। पहले पूरी इनवॉइस न मिलने पर भी 100 फीसदी दावा मिल जाता था। लेकिन नवंबर के सर्कुलर में लगी बंदिश के मुताबिक जितना इनवॉइस दिख रहा है, उस पर आईटीसी का दावा तो मिलेगा लेकिन जिसका इनवॉइस नहीं होगा, उसका 20 फीसदी ही आईटीसी का दावा किया जा सकता है। ऐसे में शेष इनवॉइस पर आईटीसी का दावा फंस जाता है, जो बाद में छोटे कारोबारी द्वारा तिमाही रिटर्न भरने पर मिलेगा।

नरमी भांप शुरू कर दी थी दरों में कटौती : शक्तिकांत दास

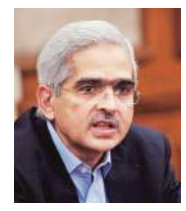

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने सोमवार को कहा कि केंद्रीय बैंक ने समय से पहले ही आर्थिक वृद्धि की रफ्तार सुस्त पड़ने की स्थिति को भांप लिया था और यही वजह है कि उसने नरमी की आहट से पहले ही फरवरी से नीतिगत दर में कटौती शुरू कर दी थी।

दास ने कहा कि देश का रिजर्व बैंक आर्थिक नरमी, मुद्रास्फीति में वृद्धि, बैंकों और एनबीएफसी की वित्तीय हालत को दुरुस्त करने के लिए जो भी जरूरी होंगे वह कदम उठाएगा। उन्होंने कहा कि फरवरी में आरबीआई के नीतिगत ब्याज दर में कटौती के फैसले से बाजार हैरान था। मुझे आश्चर्य है कि अब दरों में कटौती को रोकने के फैसले पर भी बाजार हैरान दिख रहा है। उन्होंने कहा कि आरबीआई ने बैंकों और नकदी संकट से जूझ रहे एनबीएफसी क्षेत्र की मदद के लिए कई नीतियां पेश की हैं।

कई राज्यों में फैला विरोध, मोदी की शांति की अपील

एजेंसियां
नई दिल्ली, 16 दिसंबर

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के नदवा कॉलेज में सोमवार को आंदोलनकारी छात्रों और पुलिस में भिड़ंत। *फोटो : पीटीआई*

दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में पुलिस कार्रवाई और नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर व्याप्त आक्रोश आज देश के कई शिक्षण संस्थानों तक फैल गया। नेता और नागरिक समाज के लोग छात्रों का साथ देते नजर आए। दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में रविवार को हुई हिंसा के बाद आज विरोध की आग दिल्ली, केरल, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश समेत देश के विभिन्न हिस्सों में पहुंच गई।

उच्चतम न्यायालय ने विरोध प्रदर्शनों के दौरान दंगे और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाए जाने पर कड़ा संज्ञान लिया और कहा कि यह तत्काल रुकना चाहिए। छात्रों पर पुलिस ज्यादती के आरोप लगाने वाली याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई होगी।

इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंसक प्रदर्शन दुर्भाग्यपूर्ण और बेहद निराशाजनक हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा, 'संशोधित नागरिकता कानून स्वीकार्यता, सौहार्द, करुणा और भाईचारे की भारत की सदियों पुरानी संस्कृति की व्याख्या करता है। हम निहित स्वार्थ वाले समूहों को हमें बांटने और गड़बड़ी पैदा करने की इजाजत नहीं दे सकते।'

उधर, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में एक विशाल रैली निकाली। इस बीच असम के वित्त मंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने कहा है कि नागरिक कानून में संशोधन से राज्य में अधिकतम 5.42 लाख लोगों को फायदा मिलेगा। कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्रों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में पार्टी के नेताओं ने इंडिया गेट पर धरना दिया।

जामिया में पुलिस की कार्रवाई के विरोध में लखनऊ के नदवा कॉलेज, हैदराबाद के मौलाना आजाद उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद विश्वविद्यालय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल के जादवपुर विश्वविद्यालय और आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास और आईआईटी मुंबई, आईआईएम, अहमदाबाद, भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलूरु, बंबई स्थित टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के छात्रों ने भी एकजुटता दिखाई और प्रदर्शन किया।

■ संबंधित खबर : पृष्ठ 14

प्रदर्शनों का अर्थव्यवस्था पर असर नहीं : सीतारमण

बीएस संवाददाता
मुंबई, 16 दिसंबर

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कहा कि नागरिकता कानून के खिलाफ देश के कई हिस्सों में हो रहे बवाल से आर्थिक चुनौतियों से निपटने की सरकार की कोशिशों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सीतारमण ने टाइम्स नेटवर्क के कार्यक्रम इंडिया इकनोमिक कॉन्क्लेव में कहा, 'मुझे नहीं लगता है कि इससे अर्थव्यवस्था की चुनौतियां और उससे निपटने की लिए सरकार की कोशिशों पर कोई असर पड़ेगा। मैं व्यक्तिगत रूप से और प्रधानमंत्री के साथ मिलकर उद्योग के हर क्षेत्र के साथ बात करूंगी और यह सुनिश्चित करूंगी कि उनकी सभी जरूरतें पूरी हों और चुनौतियां दूर हों।' नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे हैं। (शेष पृष्ठ 14 पर)

व्यापार गोष्ठी

सहकारी बैंकों की व्यवस्था कैसे हो दुरुस्त?

अपनी राय पासपोर्ट साइज फोटो और पूरे पते के साथ हमें इस पते पर भेजें :

बिज़नेस स्टैंडर्ड , नेहरू हाउस, 4 बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002 फैक्स नंबर - 011-23720201
या फिर ई-मेल करें goshthi@bsmail.in
अपने विचार आप हमें bshindi.com पर भी भेज सकते हैं

आज का सवाल

क्या जीएसटी क्षतिपूर्ति की किस्त मिलने से दूर होगी राज्यों की नाराजगी?

www.bshindi.com पर राय भेजें।
आप अपना जवाब एसएमएस भी कर सकते हैं। यदि आपका जवाब हां है तो **BSP Y** और यदि न है तो **BSP N** लिखकर **57007** पर भेजें।

पिछले सवाल का नतीजा

क्या अतिरिक्त प्रोत्साहन से प्रदूषण नियंत्रण पर सक्रियता दिखाएंगे राज्य? हां **57.14%** नहीं **42.86%**

खबरों में रहे स्टॉक

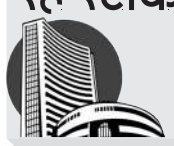

बीजीआर एनर्जी सिस्टम्स

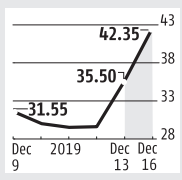

तमिलनाडु उत्पादन एवं वितरण निगम से मिला 4,443 करोड़ रु. का ऑर्डर

₹ 35.50 पिछला बंद भाव
₹ 42.35 आज का बंद भाव
▲ 19.30 %

आईटीसी

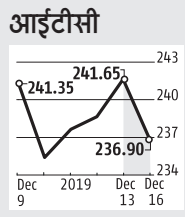

एसऐंडपी बीएसई सेंसेक्स में सबसे अधिक गिरने वाला शेयर

₹ 241.65 पिछला बंद भाव
₹ 236.90 आज का बंद भाव
▼ 1.97 %

इंटरग्लोब एविएशन

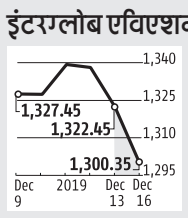

बाजार पूंजीकरण 50 हजार करोड़ रुपये से नीचे

₹ 1,322.45 पिछला बंद भाव
₹ 1,300.35 आज का बंद भाव
▼ 1.67 %

ऐबट इंडिया

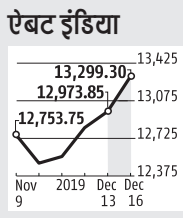

नई दवाओं और मौजूदा मेगा ब्रांड से वृद्धि को मिली रफ्तारः सीएलएसए

₹ 12,973.85 पिछला बंद भाव
₹ 13,299.30 आज का बंद भाव
▲ 2.51 %

अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज

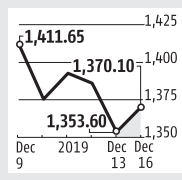

बिड़ला एमएफ ने खरीदे 7 लाख शेयर

₹ 1,353.60 पिछला बंद भाव
₹ 1,370.10 आज का बंद भाव
▲ 1.22 %

संक्षेप में

केपल लैंड का मुंबई की कंपनी संग संयुक्त उद्यम

सिंगापुर की केपल लैंड ने मुंबई की रुस्तमजी के साथ संयुक्त उद्यम बनाया है, जो मुंबई की बाहरी सीमा ठाणे में टाउनशिप विकसित करेगा। इस संयुक्त उद्यम कंपनी केपस्टोन कंस्ट्रक्शंस में केपल लैंड 49 फीसदी हिस्सेदारी का अधिग्रहण करीब 409.1 करोड़ रुपये में करेगी। *बीएस*

कोरल हब मामले में ऑडिटर पर प्रतिबंध

बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) ने केपी जोशी ऐंड कंपनी के खिलाफ सूचीबद्ध कंपनियों के ऑडिट करने की रोक लगा दी है। उस पर कोरल हब लि. के वित्तीय परिणाम बढ़ा चढ़ा कर तैयार करने के जुर्म में यह कार्रवाई की गई है। के पी जोशी के ऑडिट कंपनी के प्रवर्तक पर भी एक साल का प्रतिबंध लगाया गया है। नियामक ने सूचीबद्ध कंपनियों तथा पंजीकृत मध्यवर्ती इकाइयों के उस ऑडिट कंपनी की सेवाएं लेने पर रोक लगाई है जिनसे जोशी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं। साथ ही ऐसी कंपनियों के एक साल तक किसी तरह का ऑडिट प्रमाणन जारी करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। यह सेबी द्वारा किसी आडिटर के खिलाफ पारित पहला आदेश है। *भाषा*

आरआईएल के टावर में निवेश

कंपनी की टावर परिसंपत्तियों की खरीद पर 25,215 करोड़ रुपये लगाएगी ब्रुकफील्ड

बीएस संवाददाता
मुंबई, 16 दिसंबर

मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) की पूर्ण स्वामित्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स ऐंड होल्डिंग्स लिमिटेड (आरआईआईएचएल) ने कनाडा की ब्रुकफील्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर पार्टनर्स एलपी और उसके संस्थागत भागीदारों के साथ समझौता किया है। यह समझौता आरआईएल की दूरसंचार टावर परिसंपत्तियों में 25,215 करोड़ रुपये के निवेश के लिए किया गया है।

स्टॉक एक्सचेंजों को भेजी सूचना में आरआईएल ने कहा है कि ब्रुकफील्ड और उसके भागीदार टावर इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट से संबंधित टावरों में निवेश करेंगे। सौदे के पूरा होने पर, ट्रस्ट के पास रिलायंस जियो इन्फ्राटेल प्राइवेट लिमिटेड (आरजेआईपीएल) की 100 प्रतिशत इक्विटी शेयर पूंजी होगी। ब्रुकफील्ड ट्रस्ट द्वारा जारी किए जाने वाले 100 प्रतिशत टावरों को खरीदेगी और आरजेआईपीएल की 100 प्रतिशत इक्विटी की मालिक बन जाएगी।

आरजेआईपीएल के पोर्टफोलियो में लगभग 130,000 दूरसंचार टावर हैं जो रिलायंस जियो इन्फोकॉम के नेटवर्क की रीढ़ बने हुए हैं। अतिरिक्त टावर लगाए जाने की भी योजना है और इस तरह से टावरों की कुल संख्या 1,75,000 पर पहुंच जाने की संभावना है। 30 साल के मास्टर सर्विसेज एग्रीमेंट के तहत जियो टावर पोर्टफोलियो की प्रमुख पट्टेदार है।

आरआईएल के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने कहा, 'हम ब्रुकफील्ड के साथ यह दीर्घावधि और रणनीतिक समझौता कर बेहद उत्साहित हैं। ब्रुकफील्ड वैश्विक रूप से इन्फ्रास्ट्रक्चर परिसंपत्तियों की सबसे बड़ी और बेहद सम्मानित प्रबंधकों में से एक है। हमें भरोसा है कि ब्रुकफील्ड उच्च गुणवत्ता वाली इन्फ्रास्ट्रक्चर परिसंपत्तियों के इस विशाल पोर्टफोलियो के प्रबंधन में सफल रहेगी और इससे मूल्य वृद्धि के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा। यह सौदा भारत के डिजिटल अवसरों की संभावनाओं में वैश्विक निवेशकों के भरोसे को दर्शाता है।' इस सौदे के लिए कुछ जरूरी नियामकीय मंजूरियां भी जल्द मिल जाने की संभावना है।

जुलाई में आरआईएल ने कहा था कि आरआईआईएचएल ने 25,215 करोड़ रुपये के निवेश के लिए ब्रुकफील्ड ऐसेट मैनेजमेंट की इकाई बीआईएफ-4 जार्विस इंडिया पीटीई के साथ समझौता किया है।

निवेश समझौता

- ब्रुकफील्ड और उसके भागीदार टावर इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट से संबंधित टावरों में निवेश करेंगे
- सौदे के पूरा होने पर, ट्रस्ट के पास रिलायंस जियो इन्फ्राटेल प्राइवेट लिमिटेड की 100 प्रतिशत इक्विटी शेयर पूंजी होगी
- ब्रुकफील्ड ट्रस्ट द्वारा जारी किए जाने वाले 100 प्रतिशत टावरों को खरीदेगी और आरजेआईपीएल की 100 प्रतिशत इक्विटी की मालिक बन जाएगी

हंगरबॉक्स का 1.2 करोड़ डॉलर का निवेश दौर खत्म

करण चौधरी
बेंगलूरु, 16 दिसंबर

संस्थागत फूड टेक समाधान प्रदाता हंगरबॉक्स ने भारतीय और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के कंसोर्टियम से 1.2 करोड़ डॉलर जुटाने के साथ ही निवेश का दौर खत्म कर दिया है। कंपनी के नए निवेशकों में पेटीएम और एनपीटीके जबकि मौजूदा निवेशकों में सबरे पार्टनर्स और नियोप्लक्स शामिल हैं। इससे पहले 2018 में सबरे के नेतृत्व में 45 लाख डॉलर का निवेश दौर पूरा हुआ था।

कंपनी इस रकम का इस्तेमाल दक्षिणपूर्व एशिया में कारोबार के विस्तार और 28 भारतीय शहरों में विस्तार के अलावा मार्च 2020 तक दैनिक ऑर्डर को दोगुना करते हुए 10 लाख से अधिक करने के लिए किया जाएगा। साल 2016 में स्थापित हंगरबॉक्स प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से एंड-टु-एंड एफऐंडबी (फूड ऐंड बेवरिजेस) कारोबार के प्रबंधन समाधान उपलब्ध कराती है। हंगरबॉक्स देश के 18 शहरों में 126 बड़ी कारोबारी संस्थानों में पहले ही शामिल हो चुकी है क्योंकि इसके ग्राहकों में भारत के 11 बड़ी कंपनियों में 10 कंपनियां हैं। साथ ही इसके कर्मचारियों की संख्या 1 लाख से अधिक है।

- कंपनी के नए निवेशकों में पेटीएम और एनपीटीके भी हैं शामिल
- कंपनी इस रकम का इस्तेमाल दक्षिणपूर्व एशिया और 28 भारतीय शहरों में विस्तार पर करेगी

हंगरबॉक्स के सह-संस्थापक एवं मुख्य कार्याधिकारी संदीपन मित्रा ने कहा, 'हम त्रिआयामी रणनीति पर अमल कर रहे हैं। पहला, उद्योग जगत के साथ लगाव बढ़ाना क्योंकि देश के 18 शहरों में प्रमुख कंपनियों को हम पहले से ही सेवाएं दे रहे हैं। दूसरा, एफऐंडबी प्रबंधन में सुधार के लिए व्यापक संभावनाओं वाले क्षेत्रों में विस्तार जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा (अस्पताल) और खुदरा (मॉल) जहां पहले ही अग्रसर हो चुके हैं। तीसरा, भारत के इतर अन्य देशों में विस्तार।'

सामान्य बीमा क्षेत्र का पीएटी 90 फीसदी घटा

सुब्रत पांडा
मुंबई, 16 दिसंबर

भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) की सालाना रिपोर्ट में जारी आंकड़ों के से पता चलता है कि सामान्य बीमा उद्योग का कर-बाद लाभ (पीएटी) वित्त वर्ष 2019 में 90 प्रतिशत घटकर 683 करोड़ रुपये रह गया जो वित्त वर्ष 2018 में 6,909 करोड़ रुपये था।

सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों ने वित्त वर्ष 219 में 3,228 करोड़ रुपये का नुकसान दर्ज किया जबकि 2018 में उन्हें 2,543 करोड़ रुपये का कर-बाद लाभ हासिल हुआ था। जहां सरकार के स्वामित्व वाली सामान्य बीमा कंपनियों को ज्यादा नुकसान हुआ, वहीं निजी क्षेत्र की कंपनियों का मुनाफा वित्त वर्ष 2019 में 5 प्रतिशत घटकर 3,584 करोड़ रुपये पर रहा जो वित्त वर्ष 2018 में 3,798 करोड़ रुपये था। सामान्य बीमा उद्योग का बट्टे खाते से संबंधित नुकसान भी वित्त वर्ष 2019 में बढ़कर 22,320 करोड़ रुपये हो गया जो वित्त वर्ष 2018 के मुकाबले 45 प्रतिशत की वृद्धि है। जहां निजी क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों का बट्टे खाते से संबंधित नुकसान 38 प्रतिशत बढ़कर 3,890 करोड़ रुपये पर रहा, वहीं सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों के लिए यह 47 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 18,533 करोड़ रुपये रहा।

दूसरी तरफ, जीवन बीमा उद्योग ने 8,435.81 करोड़ रुपये का पीएटी दर्ज किया जो वित्त वर्ष 2018 में 8,511.99 करोड़ रुपये था। परिचालन से जुड़ी 24 जीवन बीमा कंपनियों में से 22 कंपनियों ने मुनाफा दर्ज किया। वर्ष के दौरान एलआईसी द्वारा दर्ज कुल लाभ पूर्व के 2,446.41 करोड़ रुपये की तुलना में 2,688.50 करोड़ रुपये रहा। निजी क्षेत्र की बीमा कंपनियों ने संयुक्त रूप से 6,064.32 करोड़ रुपये की तुलना में 5,747.31 करोड़ रुपये का कर-बाद लाभ दर्ज किया।

बीमा कंपनियों के आंकड़ों पर एक नजर

सामान्य और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों कर कर-बाद लाभ करोड़ रुपये में

बीमा कंपनियां	वित्त वर्ष 2019	वित्त वर्ष 2018
सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियां	-3287.9	2542.7
निजी क्षेत्र की बीमा कंपनियां	3584.43	798.33
'स्टैंडएलॉन' स्वास्थ्य बीमा कंपनियां	-298	-102.19
'स्पेशलाइज्ड' स्वास्थ्य बीमा कंपनियां	684.71	669.95
कुल	683.21	6,908.80

सामान्य और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के बट्टे खाते की रकम

बीमा कंपनियां	वित्त वर्ष 2019	वित्त वर्ष 2018
सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियां	-12,602.57	-18,532.95
निजी क्षेत्र की बीमा कंपनियां	-2,085.43	-2,889.87
'स्टैंडएलॉन' स्वास्थ्य बीमा कंपनियां	-435.73	-568.22
'स्पेशलाइज्ड' स्वास्थ्य बीमा कंपनियां	-217.69	-328.45
कुल	-15,341.41	-22,319.50

ऐपल ऐप स्टोर पर एमएक्स प्लेयर अग्रणी

भारत के वीडियो स्ट्रीमिंग बाजार में उतरने वाली सबसे नई कंपनी एमएक्स प्लेयर लगातार अपनी रफ्तार बढ़ाते हुए अग्रणी स्थिति हासिल कर ली है। टेनसेंट के निवेश वाली कंपनी ऐपल ऐप स्टोर की शीर्ष मुफ्त ऐप की सूची में शामिल हो गई है। जबकि गूगल प्ले स्टोर पर यह समान श्रेणी में नौवें पायदान पर है। ऐप स्टोर की रैंकिंग उपयोगकर्ताओं द्वारा किए गए डाउनलोड और उपयोगिता पर आधारित है। एमएक्स प्लेयर के मुख्य कार्याधिकारी करण बेदी ने कहा, 'इससे पता चलता है कि एमएक्स प्लेयर भारत में उपयोगकर्ताओं के लिए एक डिफॉल्ट वीडियो ऐप है।' एमएक्स प्लेयर का स्वामित्व टाइम्स इंटरनेट के पास है जिसने जून 2018 में 14 करोड़ डॉलर के एक सौदे के तहत दक्षिण कोरिया की कंपनी से यह प्लेटफॉर्म खरीदा था। उस समय यह दुनिया भर में सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला मोबाइल वीडियो प्लेयर था। *बीएस*

टर्बो एविएशन लाएगी विमानन सेवा

बीएस संवाददाता
हैदराबाद, 16 दिसंबर

ब्रिटेन का एक कारोबारी समूह हैदराबाद की कंपनी टर्बो एविएशन में बहुलांश हिस्सेदारी के अधिग्रहण के जरिये भारतीय विमानन क्षेत्र में उतरने की योजना बना रहा है। टर्बो एविएशन अगले साल से शुरू उड़ान योजना के तहत हवाई यात्रा सेवा के परिचालन के लिए एक नई विमानन कंपनी शुरू करने की योजना बना रही है। नई विमानन सेवा को 'टूस्टार' नाम दिया गया है। वी उमेश द्वारा स्थापित कंपनी टर्बो एविएशन ने इससे पहले टूजेट वाणिज्यिक विमानन सेवा शुरू की थी। इसके अलावा उसने विमानों के रखरखाव और ग्राउंड क्लियरेंस सेवाएं भी शुरू की थी।

टर्बो एविएशन के प्रबंध निदेशक वी उमेश ने कहा, 'हमने टर्बो एविएशन में बहुलांश हिस्सेदारी बेचने के लिए ब्रिटेन के एक बड़े कारोबारी समूह के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। सुरक्षा मंजूरी मिलने के बाद हम अपने साझेदार के नाम और जानकारी की घोषणा करेंगे।' टूस्टार का परिचालन शुरू होना अभी बाकी है लेकिन उसे उड़ान योजना के तहत उत्तर प्रदेश सहित सात राज्यों में 10 मार्ग पहले ही आवंटित कर दिए गए हैं।

कंपनी के रणनीतिक निवेशक ने इस विमानन कंपनी के परिचालन में अगले पांच साल के दौरान 10 करोड़ पाउंड यानी करीब 950 करोड़ रुपये के निवेश की योजना बनाई है। टूस्टार ने 5 एटीआर और 5 एयरबस 320 विमानों के शुरुआती बेड़े के साथ अगले साल फरवरी से मार्च के दौरान परिचालन शुरू करने की योजना बनाई है। कंपनी जल्द ही देश भर में परिचालन के लिए आवेदन करेगी क्योंकि विदेशी साझेदार कुछ समय बाद एक बड़ी भारतीय विमानन कंपनी स्थापित करना चाहती है।

नई विमानन कंपनी शुरू करने के बारे में बताते हुए उमेश ने कहा, 'हवाई अड्डा परिचालन हो अथवा विमानन सेवा कारोबार, भारतीय विमानन क्षेत्र मौजूदा आर्थिक मंदी से 1 फीसदी भी प्रभावित नहीं हुआ है। इससे साफ पता चलता है कि घरेलू विमानन सेवा में नए ऑपरेटरों के लिए कितनी कारोबारी संभावनाएं मौजूद हैं।' उन्होंने कहा, 'भारत में फिलहाल केवल चार बड़ी विमानन कंपनियां मौजूद हैं। ऐसे में जाहिर तौर पर नई कंपनियों के लिए संभावनाएं मौजूद हैं। उड़ान योजना के तहत घरेलू हवाई यात्रा में विस्तार के लिए 40 से 50 नए हवाई अड्डे पहले ही तैयार हो चुके हैं और भविष्य में ऐसे कई हवाई अड्डे बनने वाले हैं।'

परिचालन शुरू होने पर टूस्टार ऐसी पहली भारतीय वाणिज्यिक विमानन कंपनी होगी जो मेड इन इंडिया ड्रोनियर का इस्तेमाल करेगी। कंपनी ने उत्तर प्रदेश में कुछ मार्गों पर इसका परिचालन शुरू करने की योजना बनाई है। टूस्टार को आवंटित मार्गों में उत्तर प्रदेश में चार मार्गों के अलावा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक और गोवा के बीच तीन मार्ग शामिल हैं। इसके अलावा हैदराबाद व आंध्र प्रदेश के प्रकाशम बैराज और चेन्नई एवं तमिलनाडु के रामनाड के बीच दो मार्ग शामिल हैं। रायपुर, राउरकेला, झारसुगुडा, जगदलपुर को भुवनेश्वर, विशाखापत्तनम और हैदराबाद से जोड़ने वाले मार्ग भी आवंटित किए गए हैं।

विस्तारा के सीईओ का इस्तीफा

टाटा समूह की विमानन कंपनी विस्तारा ने सोमवार को कहा कि संजीव कपूर ने कंपनी के मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी (सीसीओ) के पद से इस्तीफा दे दिया। विमानन कंपनी के मुख्य रणनीति अधिकारी विनोद कन्नन कपूर की जगह सीसीओ का पद संभालेंगे। विस्तारा ने बयान में कहा कि कपूर ने निजी कारणों से कंपनी छोड़ी है। विस्तारा एयरलाइंस टाटा और सिंगापुर एयरलाइंस का संयुक्त उद्यम है। *भाषा*

इंडियन ऑयल को पछाड़ रिलायंस बनी नंबर वन

देव चटर्जी
मुंबई, 16 दिसंबर

रिलायंस इंडस्ट्रीज (आरआईएल) वर्ष 2019 के लिए फॉर्च्यून इंडिया 500 सूची में राजस्व के मोर्चे पर इंडियन ऑयल को पछाड़कर भारत की शीर्ष कंपनी बन गई है। वित्त वर्ष 2019 में आरआईएल का राजस्व 5.81 लाख करोड़ रुपये रहा जबकि इंडियन ऑयल का राजस्व 5.36 लाख करोड़ रुपये। वर्ष 2010 में पहली बार यह सूची प्रकाशित हुई थी और तभी से इंडियन ऑयल शीर्ष पायदान पर बरकरार रही है।

फॉर्च्यून इंडिया 500 सूची में शीर्ष पायदान पर पहुंचने की दौड़ में आरआईएल को संगठित खुदरा एवं दूरसंचार जैसे उपभोक्ता केंद्रित कारोबार से रफ्तार मिली। मुनाफे के मोर्चे पर भी मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली कंपनी आरआईएल अग्रणी रही। वित्त वर्ष 2019 में आरआईएल ने 39,588 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभा दर्ज किया जबकि इंडियन ऑयल का शुद्ध मुनाफा 17,377 करोड़ रुपये रहा। पिछले 10 वर्षों में आरआईएल का मुनाफा इंडियन ऑयल के मुकाबले औसतन 3.01 गुना अधिक रहा। वित्त वर्ष 2015 में यह आंकड़ा सबसे अधिक था जब आरआईएल का मुनाफा 4.8 गुना अधिक दर्ज किया गया।

वर्ष 2019 की सूची की एक अन्य दिलचस्प पहलू सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन में अंतर है। सूची में शामिल सार्वजनिक क्षेत्र के 22 में से 14 बैंकों का एकीकृत घाटा 74,253 करोड़ रुपये रहा जबकि निजी क्षेत्र के 24 बैंकों (विदेशी बैंकों और सहकारी बैंकों के साथ) ने 60,747 करोड़ रुपये का एकीकृत मुनाफा दर्ज किया जो वित्त वर्ष 2018 के मुकाबले 6.16 फीसदी अधिक है।

निजी क्षेत्र के महज दो बैंकों ने घाटा दर्ज किया। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को 1,908 करोड़ रुपये का घाटा हुआ जबकि लक्ष्मी विलास बैं ने 894 करोड़ रुपये का घाटा दर्ज किया। सड़क, बिजली और इस्पात क्षेत्र में फंसे हुए ऋण के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को भारी नुकसान हुआ। इनमें से अधिकतर कंपनियां अब देश की विभिन्न अदालतों में दिवालिया प्रक्रिया से जूझ रही है।

शीर्ष 500 की सूची से यह भी पता चलता है कि 2019 में इन कंपनियों के एकीकृत राजस्व और मुनाफे में क्रमश: 9.53 फीसदी और 11.8 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई। जबकि 57 कंपनियों को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और निजी क्षेत्र के अंडरटेटिंग क्षेत्र में सुदृढ़ीकरण सहित तमाम कारणों से नुकसान हुआ। शीर्ष 500 कंपनियों ने वित्त वर्ष 2019 में 4.55 लाख करोड़ रुपये का एकीकृत मुनाफा और 91.7 लाख करोड़ रुपये राजस्व दर्ज किया।

सूची में शामिल कुल 65 कंपनियों ने 1.67 लाख करोड़ रुपये का एकीकृत घाटा दर्ज किया जबकि पिछले साल 79 कंपनियों ने 2 लाख करोड़ रुपये का घाटा दर्ज किया था। इस सूची में कंपनियों की सहायक इकाइयों को शामिल नहीं किया गया है। अधिग्रहण के कई मामलों में अधिग्रहीत कंपनियां बाहर हो गई जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन का अधिग्रहण ओएनजीसी ने किया, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन का अधिग्रहण पावर फाइनैंस कॉरपोरेशन ने किया और विजया बैंक एवं देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में हो गया।

निजी क्षेत्र में भी सुदृढ़ीकरण दिखा जहां भूषण स्टील का अधिग्रहण टाटा स्टील और एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी कैपिटल फर्स्ट ने किया। इसके अलावा आईडीएफसी बैंक के विलय से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का उदय हुआ। तेल एवं गैस क्षेत्र की आई कंपनियों का एकीकृत राजस्व इस सूची में शामिल 500 कंपनियों के कुल राजस्व का करीब 22.3 फीसदी रहा। जबकि बैंकिंग क्षेत्र के मामले में यह आंकड़ा 15.88 फीसदी रहा। बैंकिंग क्षेत्र ने 48 कंपनियों के साथ इस सूची में सबसे अधिक योगदान किया। जबकि मुनाफे में तेल एवं गैस क्षेत्र की हिस्सेदारी 23.44 फीसदी पर सर्वाधिक रही।

इन्फोटेक क्षेत्र की 20 कंपनियों का एकीकृत राजस्व सूची की 500 कंपनियों के कुल राजस्व का 4.98 फीसदी रहा लेकिन मुनाफे के मोर्चे पर 16.17 फीसदी के साथ उसकी दूसरी सबसे बड़ी हिस्सेदारी रही। सूची में शामिल 500 कंपनियों के कुल कर्मचारी लागत में इस साल 7.26 फीसदी की वृद्धि हुई जबकि एक साल पहले यह आंकड़ा 10.22 फीसदी रहा था।

राजस्व और मुनाफे में बढ़ोतरी

(करोड़ रुपये में)

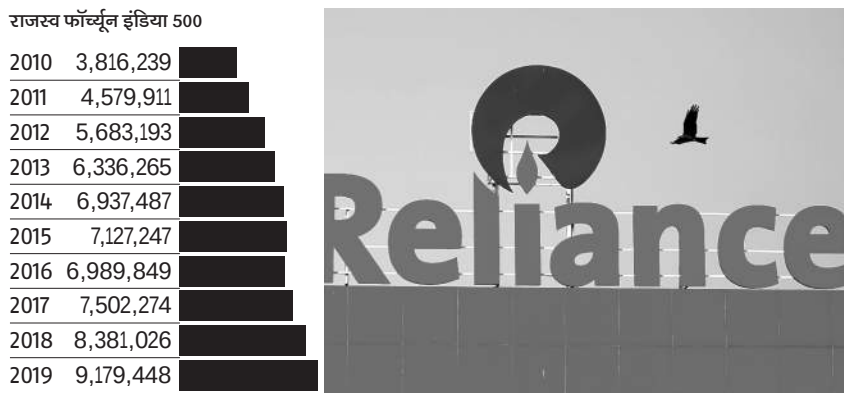

राजस्व फॉर्च्यून इंडिया 500

2010	3,816,239
2011	4,579,911
2012	5,683,193
2013	6,336,265
2014	6,937,487
2015	7,127,247
2016	6,989,849
2017	7,502,274
2018	8,381,026
2019	9,179,448

मुनाफा फॉर्च्यून इंडिया 500

2010	330,824
2011	411,323
2012	392,336
2013	415,307
2014	433,992
2015	408,229
2016	375,801
2017	453,218
2018	407,223
2019	455,293

स्रोतः फॉर्च्यून इंडिया 500, फॉर्च्यून इंडिया रिसर्च

आर्सेलरमित्तल व निप्पॉन ने किया एस्सार का अधिग्रहण

ईशिता आयान दत्त और सोमेश झा
कोलकाता/नई दिल्ली, 16 दिसंबर

विश्व की सबसे बड़ी स्टील निर्माता आर्सेलरमित्तल ने निप्पॉन स्टील के साथ मिलकर एस्सार स्टील के लेनदारों के साथ 42,000 करोड़ रुपये का सौदा पूरा कर लिया। आर्सेलरमित्तल ने एक बयान में कहा कि निप्पॉन स्टील कॉरपोरेशन के साथ स्थापित संयुक्त उद्यम आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया लिमिटेड के पास एस्सार स्टील का स्वामित्व होगा और वही इस कंपनी का परिचालन करेगी। इस कंपनी में आर्सेलरमित्तल की हिस्सेदारी 60 फीसदी होगी जबकि निप्पॉन स्टील के पास बाकी हिस्सेदारी होगी।

आर्सेलरमित्तल ने ऐलान किया कि आर्सेलरमित्तल के अध्यक्ष व सीएफओ आदित्य मित्तल को आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है जबकि दिलीप उम्मेन को कंपनी का मुख्य कार्याधिकारी बनाया गया है।

मित्तल की नियुक्ति से हालांकि उद्योग की कंपनियों को आश्चर्य नहीं हुआ है। एस्सार के अधिग्रहण में उन्होंने अहम भूमिका निभाई और अदालत में हो रही सुनवाई के दौरान भी उन्हें देखा गया था। उम्मेन अभी एस्सार स्टील के प्रबंध निदेशक हैं।

परिचालन पर नियंत्रण हासिल करने के लिए मित्तल व निप्पॉन के अधिकारी मंगलवार को हजीरा प्लांट का दौरा कर सकते हैं। यह सौदा पूरा होना दिवालिया संहिता के लिए काफी अहम है, हालांकि यह 865 दिन बाद हासिल हुआ और वित्तीय लेनदारों को उनके दावे का 90 फीसदी से ज्यादा मिल रहा है।

वित्तीय लेनदारों के कुल स्वीकार्य दावे 49,473 करोड़ रुपये हैं, जिसमें से भारतीय स्टेट बैंक का कर्ज सबसे ज्यादा 13,226 करोड़ रुपये है।

एसबीआई के चेयरमैन रजनीश कुमार ने दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा, सबसे महत्वपूर्ण मामलों में से एक एस्सार स्टील का निपटान आज हो गया। यह तीसरी तिमाही में बैंक का लाभ मजबूत बनाएगा और अर्थव्यवस्था के लिए यह काफी सकारात्मक होगा।

हजीरा संयंत्र और मित्तल के लिए यह समाधान नए अध्याय की शुरुआत का संकेत दे रहा है। आर्सेलरमित्तल के चेयरमैन व सीईओ लक्ष्मी मित्तल ने कहा, एस्सार स्टील का अधिग्रहण आर्सेलरमित्तल के लिए अहम रणनीतिक कदम है। भारत को हमारी कंपनी काफी समय से आकर्षक बाजार मानती रही है और हम अच्छे मौके की तलाश कर रहे थे।

उन्होंने कहा, भारत और एस्सार की अपील स्थायी है। एस्सार का परिचालन लाभकारी है और साइट अच्छी जगह पर है। साथ ही भारतीय अर्थव्यवसस्था के लिए लंबी अवधि की बढ़त की क्षमता भी है, इसलिए भारतीय स्टील की मांग के बारे में अच्छी तरह से पता है।

लक्ष्मी मित्तल ने यह भी कहा कि निप्पॉन की संयुक्त ताकत नए मौके लाएगी, जो हमें साल 2030 तक 30 करोड़ टन सालाना स्टील उत्पादन क्षमता के लक्ष्य में सकारात्मक योगदान देने की अनुमति देगा।

यह अधिग्रहण नई कंपनी को भारत का चौथा सबसे बड़ा स्टील उत्पादन बना देगा और पश्चिम भारत की सबसे बड़ी स्टील कंपनी। इसकी मौजूदा सालाना क्रूड स्टील उत्पादन क्षमता 75 लाख टन है। इसके अतिरिक्त पूवी. भारत में आयरन ओर पैलेट संयंत्र है और उसकी मौजूदा सालाना क्षमता 1.4 करोड़ टन है।

आने वाले समय में यानी मध्यम अवधि में उत्पादन क्षमता 85 लाख टन करने और लंबी अवधि में तैयार स्टील का निर्यात 1.2 करोड़ टन से 1.5 करोड़ टन करने का लक्ष्य है। एस्सार की समाधान योजना ने 18,697 करोड़ रुपये के पूंजीगत खर्च का भी संकेत दिया है, जो अगले छह साल में दो चरणों में लागू की जाएगी।

आर्सेलरमित्तल के अध्यक्ष और सीएफओ आदित्य मित्तल ने कहा, यह अधिग्रहण हमें आगामी दशकों में भारत में होने वाले बुनियादी ढांचे के विस्तार और शहरीकरण में योगदान का मौका देगा। उन्होंने कहा, इसके लिए हमें लक्षित पूंजीगत खर्च की योजना लागू करनी होगी।

निप्पॉन स्टील के निदेशक और अध्यक्ष ई हासिमोतो ने कहा, निप्पॉन स्टील और आर्सेलरमित्तल नई कंपनी को अपने-अपने अनुभव मुहैया कराएगी और तकनीक भी उपलब्ध कराएगी ताकि वह समाधान योजना को तेजी से लागू कर करे और कारोबारी विस्तार कर सके।

दिवालिया संहिता को मिलेगी ताकत

आईबीसी के तहत आरबीआई की अनिवार्य समाधान वाली पहली 12 कंपनियों की सूची में एक एस्सार थी। इसका समाधान पूरा होने के साथ ही आरबीआई की पहली सूची की छह कंपनियों के समाधान के तहत कुल मिलाकर वित्तीय लेनदारों को स्वीकार्य दावे का 56.86 फीसदी मिला है जबकि औसत 42 फीसदी का है।

लक्ष्मी मित्तल ने कहा, यह लेनदेन बताता है कि भारत को किस तरह से दिवालिया संहिता से फायदा मिला है। यह ऐसा सुधार है जिसका सकारात्मक असर भारतीय अर्थव्यवस्था में हर तरफ महसूस किया जाएगा।

एसबीआई के चेयरमैन रजनीश कुमार ने कहा कि एस्सार के मामले ने आईबीसी प्रक्रिया के तहत करीब-करीब हर मसले का निपटान किया है। इस मामले में काफी मुकदमेबाजी हुई, जिसने दिवालिया संहिता की धाराओं की परख पिछले दो वर्षों में की। कुमार ने हालांकि कहा कि आईबीसी प्रक्रिया का शुरुआती फायदा लेने के मामले में अभी भी देनदार और लेनदार के बीच असमंजस देखा जा रहा है।

एस्सार स्टील का दिवालिया समाधान हुआ पूरा

- आदित्य मित्तल को आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है जबकि दिलीप उम्मेन को कंपनी का मुख्य कार्याधिकारी बनाया गया है
- परिचालन पर नियंत्रण हासिल करने के लिए मित्तल व निप्पॉन के अधिकारी मंगलवार को हजीरा प्लांट का दौरा कर सकते हैं
- यह अधिग्रहण नई कंपनी को भारत का चौथा सबसे बड़ा स्टील उत्पादन बना देगा और पश्चिम भारत की सबसे बड़ी स्टील कंपनी।
- वित्तीय लेनदारों के कुल स्वीकार्य दावे 49,473 करोड़ रुपये हैं, जिसमें से भारतीय स्टेट बैंक का कर्ज सबसे ज्यादा 13,226 करोड़ रुपये है

लंबी आर्थिक मंदी से बढ़ेगा खुदरा एनपीए : मूडीज

अभिजित लेले
मुंबई, 16 दिसंबर

रेटिंग एजेंसी मूडीज के मुताबिक पिछली कुछ तिमाहियों से सुस्त हो रही भारत की आर्थिक रफ्तार से पुनर्भुगतान की पारिवारिक इकाई की क्षमता प्रभावित होगी और खुदरा कर्ज की गुणवत्ता पर चोट पहुंचेगी।

निजी क्षेत्र के बैंकों ने ज्यादा खुदरा कर्ज दिया है और ये बैंक ज्यादा जोखिम के दायरे में हो सकते हैं। हालांकि गैर-निष्पादित कर्ज में इजाफा धीरे-धीरे होगा। मूडीज ने एक बयान में कहा कि भारत की बढ़त की रफ्तार घटी है क्योंकि निवेश की अगुआई में यह मंदी अब व्यापक होकर उपभोग को कमजोर कर रही है। ग्रामीण परिवारों के बीच वित्तीय दबाव और नौकरियों के सृजन में सुस्ती इस मंदी को आगे बढ़ाने वाले अहम संकेतक हैं।

हाल के वर्षों में खुदरा कर्ज मुहैया कराने वाले अहम गैर-बैंक वित्तीय संस्थानों (एनबीएफआई) में नकदी संकट ने कमजोर हालात में और इजाफा किया है। हालांकि परिवारों के लिए आय का झटका कई वर्षों में कम हुआ है, लेकिन बढ़त पर इसका असर तब तक स्पष्ट नहीं दिकेगा जब तक कि परिवार कर्ज न ले। उधारी की आपूर्ति को लेकर मामला ठीक होने से अब ऐसे दोहरे संकट का बढ़त पर असर स्पष्ट दिख गया है।

रेटिंग एजेंसी को अगले साल चक्रीय सुधार की उम्मीद है, हालांकि बढ़त की रफ्तार विगत के मुकाबले कमजोर रहेगी। परिवारों के बीच मांग में नरमी का असर प्रतिभूति जारी करने वाली विभिन्न क्षेत्र की कंपनियों पर नकारात्मक असर पड़ेगा।

देसी मांग में इजाफे के लिए सरकार ने कई कदमों का ऐलान किया है और इस तरह से आर्थिक मंदी से निपट रही है। सरकार ने किसानों व कम आय वाले परिवारों के लिए आय के सहारे का ऐलान किया है

नकदी बचाकर निवेश में देर कर रहे म्युचुअल फंड

विशेषज्ञों ने कहा, फंड मैनेजर शेयर कीमतों के जाल में नहीं फंसना चाहते

जश कृपलानी
मुंबई, 16 दिसंबर

नवंबर में इक्विटी निवेश में तेज गिरावट कुछ फंड मैनेजरों (खास तौर से मिडकैप व स्मॉलकैप क्षेत्र में) के लिए शायद राहत लेकर आई होगी, जहां एक दर्जन से ज्यादा इक्विटी योजनाएं अभी 7 फीसदी से लेकर 20 फीसदी तक नकदी बचाकर रखे हुए है।

उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा, निवेशकों से निवेश आकर्षित करती रही योजनाएं अभी निवेशकों की पूरी रकम के निवेश का उचित मौका नहीं खोज पाई है। मॉर्निंगस्टार के निदेशक (फंड रिसर्च) कौस्तुभ बेलापुरकर ने कहा, स्मॉल व मिडकैप योजनाओं में निवेशकों की काफी रुचि देखने को मिली थी। मिडकैप क्षेत्र अभी भी जरूरत से ज्यादा मूल्यांकन वाले क्षेत्र पर नजर डाल रहा है। ऐसे में फंड मैनेजर इस क्षेत्र में कुछ ही शेयर चुन पा रहे हैं, साथ ही रकम के निवेश से पहले उचित कीमत का इंतजार कर रहे हैं।

एक दर्जन से ज्यादा इक्विटी योजनाएं अभी 7 फीसदी से लेकर 20 फीसदी तक नकदी बचाकर रखे हुए है

फंड मैनेजरों ने कहा कि इंडेक्स में हालांकि कुछ गिरावट दर्ज हुई है, लेकिन गुणवत्ता वाली मिडकैप कंपनियों के शेयर ज्यादा महंगे हो गए हैं।

एक फंड मैनेजर ने कहा, पिछले साल निफ्टी मिडकैप, निफ्टी के मुकाबले खासे प्रीमियम पर ट्रेड र हे थे, लेकिन अब काफी छूट पर ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि ठीक-ठाक बढ़त की क्षमता से लैस अच्छी गुणवत्ता वाले मिडकैप शेयर ज्यादा महंगे हो गए हैं।

फंड मैनेजर ने कहा, दूसरी ओर अगर हम पिटे हुए शेयर पर नजर डालें तो उनकी कीमत के जाल में फंसने का जोखिम है, खास तौर से मौजूदा परिस्थितियों में जब अलग-अलग कारोबार में अवरोध नजर आ रहा है।

स्मॉलकैप योजनाएं औसतन सात फीसदी नकदी रखे हुए है, वहीं मिडकैप योजनाओं के पास पांच फीसदी से ज्यादा नकदी है। दिलचस्प रूप से लार्जकैप के पास भी नकदी जमा हो रहा है, खास तौर से ब्लूचिप शेयरों पर ध्यान केंद्रित करने वाली योजनाओं में।

प्राइमइन्वेस्टर डॉट इन की सह-संस्थापक विद्या बाला ने कहा, लार्जकैप में ब्लूचिप में काफी तेजी दिखी है और फंड मैनेजर इनमें पोजीशन लेने के लिए उचित मूल्यांकन का इंतजार करना चाहेंगे।

सोमवार को 30 शेयरों वाला सेंसेक्स लाल निशान में बंद होने से पहले 41,185 अंक के सर्वोच्च स्तर को छू गया था।

ब्लूचिप शेयरों पर केंद्रित योजनाएं औसतन 6.2 फीसदी नकदी पर बैठी हुई है और यह जानकारी वैल्यू रिसर्च के आंकड़ों से मिली।

नवंबर में इक्विटी निवेश 78 फीसदी घटकर 1,311 करोड़ रुपये रह गया था, जो साढ़े तीन साल का निचला स्तर है। मिडकैप योजनाओं में निवेशकों का निवेश 26 फीसदी घटकर 801 करोड़ रुपये रहा है जबकि स्मॉलकैप में 61 फीसदी घटकर 261 करोड़ रुपये।

उद्योग पर नजर रखने वालों ने कहा, नकदी बचाए रखने से वास्तव में फंड मैनेजरों को मौजूदा माहौल में गिरावट को सीमित करने में मदद करता है, लेकिन ज्यादा नकदी व्यापक बाजार की तेजी में फायदा न उठा पाने का जोखिम भी सामने रखता है।

फ्रैंकलिन एमएफ ने एस्सेल की एक और फर्म में ली कटौती

जश कृपलानी
मुंबई, 16 दिसंबर

फ्रैंकलिन टेम्पलटन म्युचुअल फंड ने एस्सेल समूह की एक और फर्म और डीएनए अखबार की परिचालक डिलिजेंट मीडिया कॉरपोरेशन में किए गए निवेश पर 50 फीसदी की कटौती ली है।

फंड हाउस ने डिलिजेंट मीडिया कॉरपोरेशन के गैर-परिवर्तनीय ऋणपत्र में 412 करोड़ रुपये का निवेश किया था, जो फ्रैंकलिन की पांच योजनाओं के जरिए किया गया था। इनमें बकाया ब्याज भुगतान शामिल है।

एक नोट में फ्रैंकलिन टेम्पलटन एमएफ ने कहा, डाउनग्रेड किए जाने के बाद फ्रैंकलिन टेम्पलटन एमएफ ने एनसीडी की कीमत 12 दिसंबर 2019 को फेस वैल्यू के मुकाबले 50 फीसदी घटा दी है, जो एम्फी के कटौती मानक के मुताबिक है। गौरतलब है कि इस एनसीडी को सुभाष चंद्रा ने व्यक्तिगत गारंटी भी दी है।

गुरुवार को इक्रा ने डिलिजेंट मीडिया कॉरपोरेशन की एनसीडी की रेटिंग बीबी से बी कर दी थी। एजेंसी ने कहा, लंबी अवधि के रेटिंग संशोधन में डिलिजेंट मीडिया की कमजोर नकदी व कमजोर प्रदर्शन बने रहने को ध्यान में रखा गया था।

फंड हाउस की योजनाओं के जरिए एनसीडी में हुआ निवेश जून 2020 में परिपक्व हो रहा है। इस एनसीडी में फ्रैंकलिन इंडिया इनकम ऑपरच्युनिटीज फंड, लो ड्यूरेशन फंड, डायनेमिक एक्रुअल फंड, क्रेडिट रिस्क फंड और शॉर्ट टर्म इनकम प्लान के जरिए निवेश किया गया था।

बीएमए के ग्राहकों ने सैट से मांगी मदद

सुंदर सेतुरामन
मुंबई, 16 दिसंबर

ब्रोकरेज फर्म बीएमए वेल्थ के निराश ग्राहकों ने सोमवार को प्रतिभूति अपील प्राधिकरण (सैट) से संपर्क कर उनकी प्रतिभूतियां और कोष वापस उनके डीमैट खातों में लौटाए जाने की मांग की।

सोमवार को बीएमए के ग्राहकों ने बाजार नियामक सेबी के कार्यालय के बाहर फिर से विरोध जताया। शुरू में निवेशक भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के समक्ष शिकायत दर्ज कराने की योजना बना रहे थे। हालांकि जब उन्होंने आरबीआई से संपर्क किया तो उन्हें बताया गया कि उन्हें पहले बैंक के साथ शिकायत दर्ज कराने और फिर 15 दिन तक इंतजार करने की जरूरत है, जिसके बाद ही आरबीआई इस मामले पर विचार कर सकता है।

निवेशकों ने सैट से अनुरोध किया है कि वह बैंक अधिकारियों को उनके गिरवी शेयरों और फंडस ग्राहकों को लौटाने का निर्देश दे, जैसा कि कार्वी के मामले में किया गया था। अक्टूबर 2019 में सेबी के आदेश में एनएसई की उस टिप्पणी का हवाला दिया गया कि बीएमए ने पैसा जुटाने के लिए अपने ग्राहकों की प्रतिभूतियां जेएम फाइनैंशियल, बजाज फाइनैंस, और एचडीएफसी बैंक के पास गिरवी रखीं।

बीएमए के ग्राहकों ने सैट से बीएमए वेल्थ के सभी निदेशकों की संपत्तियां जब्त करने और इसके निदेशक अनुभव भट्टर को गिरफ्तार किए जाने का अनुरोध किया है, जिसे इस घोटाले का मुख्य सूत्रधार माना गया है।

सैट के समक्ष अपनी शिकायत में निवेशकों ने कहा है कि बीएमए मामले में सेबी और एक्सचेंजों की प्रतिक्रिया सख्त नहीं दिखी है। निवेशकों का आरोप है कि उनके साथ सेबी ने वैसा व्यवहार नहीं किया जैसा कि कार्वी ब्रोकिंग के निवेशकों के मामले में देखने को मिला था। स्पष्ट है कि कार्वी ब्रोकिंग को भी इसी तरह की जांच से गुजरना पड़ा है।

बीएमए संकट

- ग्राहकों का दावा, घोटाले से 45,000 निवेशक प्रभावित हुए हैं
- बीएमए वेल्थ के ग्राहकों ने अपनी प्रतिभूतियां और पैसे पाने के लिए सैट से संपर्क साधा
- निवेशकों ने सैट से बीएमए वेल्थ के सभी निदेशकों की परिसंपत्तियां जब्त करने का अनुरोध किया
- निवेशकों का कहना है कि सेबी और एक्सचेंजों का कदम इस संबंध में अपर्याप्त है

एफपीआई, एमएफ की परिसंपत्तियों में बाजार के मुकाबले ज्यादा बढ़त

समी मोडक

भारत का कुल बाजार पूंजीकरण इस कैलेंडर वर्ष में अब तक 7.1 फीसदी (10.3 लाख करोड़ रुपये) बढ़कर 155 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) और म्युचुअल फंडों के कब्जे वाली परिसंपत्तियां (एयूसी) काफी तेजी से बढ़ी है। प्रवर्तकों से बाहर सबसे बड़े निवेशक एफपीआई की एयूसी 11.5 फीसदी (3.1 लाख करोड़ रुपये) बढ़कर 30.4 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गई, वहीं म्युचुअल फंडों की एयूसी 18.4 फीसदी (1.8 लाख करोड़ रुपये) बढ़कर करीब 12 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गई। परिसंपत्तियों में ज्यादातर बढ़त पूंजी में बढ़ोतरी के दम पर हुई, लेकिन इसमें बढ़े निवेश का ठीक-ठाक हिस्सा भी है। बीमा कंपनियों की एयूसी में 5 फीसदी से कम बढ़ोतरी हुई।

बाजार के प्रतिभागियों ने कहा कि यह इस बात का संकेत हो सकता है कि बीमा क्षेत्र की दिग्गज भारतीय जीवन बीमा निगम की इक्विटी में बढ़ोतरी बाजार से कम रही है। इस बीच, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) एक अहम निवेशक वर्ग के तौर पर उभर रहा है और इनकी परिसंपत्तियों में 16 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज हुई है।

आंकड़ों के आईने में

निवेशक श्रेणी	एयूसी* (लाख करोड़ रु.)	बदलाव लाख करोड़ रुपये में	बदलाव फीसदी में	कुल एमकैप का %
एफपीआई	30.4	3.1	11.5	20
म्युचुअल फंड	11.9	1.8	18.4	8
बीमा कंपनियां	10.0	0.4	4.5	6
एफडीआई	9.4	1.3	15.7	6
विदेशी डिपॉजिटरी	3.4	0.1	4.5	2
अन्य	6.8	1.3	4.5	4
भारत का कुल बाजार पूंजीकरण	155.0	10.3	7.1	100

* नवंबर 2019 में। अन्य में एआईएफ, बैंक, कंपनियां, पेंशन फंड शामिल, (प्रवर्तकों की हिस्सेदारी छोड़कर)
स्रोत : एनएसडीएल

सेंसेक्स की एक तिहाई कंपनियों के शेयर सस्ते

समी मोडक
मुंबई, 16 दिसंबर

बीएसई सेंसेक्स अब तक के सर्वोच्च स्तर से महज 200 अंक दूर है। लेकिन बेंचमार्क सूचकांकों के रिकॉर्ड स्तर पर रहने के बावजूद इसमें शामिल कई कंपनियों के शेयर अभी भी सस्ते दाम पर उपलब्ध हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड ने सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों की 12 महीने आगे की प्राइस टु अर्निंग (पीई) और प्राइस टु बुक (पीबी) गुणक का विश्लेषण किया और उसकी तुलना संबंधित शेयरों के 10 साल के औसत पीई और पीबी से की।

मूल्यांकन में अंतर के आधार पर इन शेयरों को सस्ते, महंगे और बाजार के मुताबिक वर्गीकृत किया गया। विश्लेषण के मुताबिक, 11 शेयर सस्ते दाम वाली श्रेणी में शामिल रहे, वहीं 14 महंगी श्रेणी में और बाकी पांच शेयरों का मूल्यांकन उनके ऐतिहासिक औसत के मुताबिक रहा। सस्ती श्रेणी वाली सूची में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों मसलन ओएनजीसी, पावर ग्रिड, एनटीपीसी, और कुछ वाहन व तकनीक क्षेत्र की कंपनियों का वर्चस्व रहा। महंगी सूची में ज्यादातर ब्लूचिप कंपनियां मसलन रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, हिंदुस्तान यूनिलीवर और एशियन पेंट्स का वर्चस्व रहा। उचित मूल्यांकन वाले शेयरों में इन्फोसिस और बजाज ऑटो शामिल रही। अभी सेंसेक्स अपने ऐतिहासिक मूल्यांकन के मुकाबले प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। सेंसेक्स अभी अगले 12 महीने की अनुमानित आय के 19.1 गुने पर कारोबार कर रहा है जबकि 10 साल का ऐतिहासिक औसत 15.8 गुना है। विश्लेषकों ने कहा कि निवेशकों को प्रीमियम मूल्यांकन से परेशान नहीं होना चाहिए और इसके बजाय शेयर विशेष में खरीदारी का मौका तलाशना चाहिए।

सेंसेक्स कंपनियों का लेखाजोखा

सस्ते	महंगे	बाजार के मुताबिक
आईटीसी	टीसीएस	भारतीय स्टेट बैंक
ओएनजीसी	एचडीएफसी बैंक	बजाज ऑटो
एचसीएल टेक	हिंदुस्तान यूनिलीवर	टेक महिंद्रा
एनटीपीसी	एचडीएफसी	इन्फोसिस
सन फार्मा	आईसीआईसीआई बैंक	वेदांत
इंडसइंड बैंक	कोटक महिंद्रा बैंक	
पावर ग्रिड	बजाज फाइनैंस	
एमऐंडएम	भारती एयरटेल	
टाटा स्टील	मारुति सुजूकी	
हीरो मोटोकॉर्प	ऐक्सिस बैंक	
लार्सन ऐंड टुब्रो	येस बैंक	
	रिलायंस इंडस्ट्रीज	
	एशियन पेंट्स	
	टाटा मोटर्स	

स्रोत : ब्लूमबर्ग संकलन : बीएस रिसर्च ब्यूरो

इन्वेस्टेक की एक रिपोर्ट में कहा गया है, मूल्यांकन के कारण भारत से दूर रहना अब सही वजह नहीं है क्योंकि हमारा मानना है कि कई शेयरों में निवेश के मौके उपलब्ध हैं और इनमें से ज्यादातर सस्ते दाम पर कारोबार कर रहे हैं, हालांकि कुल मिलाकर बाजार महंगा नजर आ रहा है। व्यापक बाजार में ध्रुवीकरण बेंचमार्क सेंसेक्स के मुकाबले ज्यादा महत्वपूर्ण है। आईडीएफसी म्युचुअल फंड के नोट में कहा गया है, जनवरी 2018 से बाजार स्पष्ट रूप से दो स्तरों में बंटा हुआ है और बीएसई-500 के 70-80 शेयर सकारात्मक रिटर्न दे रहे हैं। उच्च गुणवत्ता, स्थायी रूप से आय दर्ज करने वाले शेयरों पर ध्यान देना इस अवधि में ज्यादा कामयाब तरकीब रही है। पिछले ऐतिहासिक स्तर से मूल्यांकन में बढ़ोतरी संकेत देता है कि निवेशकों ने उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों को उनकी आय डिलिवरी के मुकाबले ज्यादा पुरस्कृत किया है।

बजट पूर्व बैठक में उठे एफपीआई, एआईएफ, म्युचुअल फंड उद्योग से जुड़े मसले, बैंक अधिकारियों और म्युचुअल फंड, बीमा और एनबीएफसी के प्रमुख आदि के साथ बैठक

वित्त क्षेत्र के प्रमुखों से मिलीं वित्तमंत्री

निधि राय
मुंबई, 16 दिसंबर

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पूर्व विभिन्न साझेदारों के साथ होने वाली रस्मी सलाह प्रक्रिया शुरू कर दी है और इस कड़ी में उन्होंने पहली मुलाकात बैंक अधिकारियों और म्युचुअल फंड, बीमा और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के प्रमुखों से की है।

इस बैठक का मुख्य उद्देश्य विभिन्न साझेदारों के सुझावों को सुनना है। बैठक के बाद भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन रजनीश कुमार ने कहा, 'समूह ने कराधान, सत्यापन, कर्ज वृद्धि में सुधार करने, वित्त बाजार की पर्याप्तता में इजाफा करने संबंधी सुझाव दिए हैं।'

बैठक में शामिल रहे सूत्रों के मुताबिक कुछ बैंक अधिकारियों ने सरकार को यह भी सुझाव दिया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र के शीर्ष छह बैंकों को लेकर चिंतित नहीं होना चाहिए बल्कि उन्हें बचे हुए छह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर ध्यान देना चाहिए। एक वरिष्ठ बैंक अधिकारी ने कहा, 'कुछ बैंक अधिकारियों की राय है कि सरकार को क्रम से सातवें, आठवें और नवें बैंक में अपनी हिस्सेदारी को घटाकर 50 फीसदी ने नीचे लाना चाहिए। सरकार को अपनी हिस्सेदारी बाजार दर के हिसाब से कम करनी चाहिए और अंतिम के तीन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सरकार सार्वजनिक-निजी भागीदारी के आधार पर चलाए।'

एनबीएफसी की प्रतिनिधि संस्था फाइनैंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल (एफआईडीसी) ने भी सरकार को अपने सुझाव दिए हैं। संस्था ने सरकार को पहला सुझाव यह दिया है कि वह सबसे पहले दीर्घ अवधि और लघु अवधि की वित्त मुहैया कराने वाली एनबीएफसी में उचित अंतर करे। वित्त मंत्री को लिखे अपने पत्र में एफआईडीसी ने कहा, 'पिछले एक वर्ष में एनबीएफसी की ओर से चूक के दो बड़े उदाहरण बुनियादी ढांचे को वित्त देने वाली एनबीएफसी और वित्त आवास कंपनी हैं। ये दोनों ही दीर्घ अवधि के लिए ऋण देती हैं और इसलिए शायद उन्हें संपत्ति और देयता के बीच असंतुलन का सामना करना पड़ता है। हालांकि, पूरे एनबीएफसी क्षेत्र को ही संपत्ति देयता असंतुलन के तौर देखा और प्रचारित किया जाता है जिसके कारण बैंक और म्युचुअल फंड अचानक जोखिम से घिर जाते हैं।'

एफआईडीसी ने इस बात पर जोर दिया है कि एनबीएफसी क्षेत्र के पास नियमित तौर पर वित्त मंत्रालय के साथ संपर्क करने के लिए कोई मंच नहीं है। पत्र में कहा गया है, 'वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाओं के विभाग को नियमित बैठकें बुलानी चाहिए।'

वित्त मंत्री को सुझाव

- सरकार को पीएसबी में अपनी हिस्सेदारी घटानी चाहिए और बैंकों में पीपीपी मॉडल को अपनाना चाहिए
- दीर्घावधि और लघु अवधि की वित्त मुहैया कराने वाली एनबीएफसी के बीच अंतर किया जाए
- वित्त मंत्रालय और एनबीएफसी के बीच नियमित संवाद के लिए प्लेटफॉर्म बने
- एनबीएफसी के वरिष्ठ अधिकारियों को पीएसयू बोर्डों में गैर-आधिकारिक निदेशक नियुक्त किया जाना चाहिए
- बैंकों को एनबीएफसी को प्राथमिकता वाले क्षेत्र के तौर ऋण देने की अनुमति दी जाए
- एनबीएफसी को सुरक्षित ऋणपत्रों/बॉन्डों को ऑन टैप जारी करने की अनुमति
- नैशनल हाउसिंग बैंक को एनबीएफसी की शीर्ष संस्था बनाई जाए
- एमएसएमई और फैक्टरी अधिनियम को पुनर्भाषित किया जाए
- पट्टा किरायेदारी पर जीएसटी को घटाकर 5 फीसदी किया जाना चाहिए

भरोसा कायम करने पर रहा जोर

श्रीमी चौधरी
नई दिल्ली, 16 दिसंबर

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ 3 घंटे तक चली बजट पूर्व बैठक में विभिन्न हिस्सेदारों और नियामक ने कुछ प्रमुख प्रस्ताव पेश किए, जिसमें इक्विटी मार्केट में कर की दरों को तार्किक बनाया जाना, कुछ श्रेणी के वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ)को बढ़ावा देना और म्युचुअल फंड उद्योग पर पड़ रहे दबाव को खत्म किया जाना शामिल है।

मामले से जुड़े दो व्यक्तियों ने कहा कि इस बैठक के दौरान विभिन्न मसले उठाए गए, जिससे घरेलू और विदेशी निवेशकों का भारत के पूंजी बाजार में भरोसा बहाल हो।

सूत्रों ने कहा कि सरकार ने इक्विटी उत्पादों पर कर की दरों पर राय मांगी और साथी यह भी जानने की कवायद की कि क्या प्रतिभूतियों पर दीर्घावधि पूंजीगत लाभ (एलटीसीजी) कर छूट 3 साल से ज्यादा समय तक व्यावहारिक है।

इसके अलावा मंत्रालय ने यह समझने की कोशिश की कि अन्य श्रेणी के फंडों जैसे बुनियादी ढांचा, सोशल वेंचर, वेंचर कैपिटल और एसएमई फंड व रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (आरईआईटी) व इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (इनविट) जैसे अन्य श्रेणी के कोषों से जुड़े मसलों को किस तरह से कम किया जा सकता है और इनकी जटिलता कम करके किस तरह इन्हे आकर्षक बनाया जा सकता है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को नई दिल्ली में वित्तीय एवं पूंजी बाजार के प्रतिनिधियों के साथ बजट-पूर्व चर्चा की। इसमें राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर एवं वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। इसके अलावा अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों से भी उन्होंने मुलाकात की और उनकी मांगों पर चर्चा की *फोटो: पीटीआई*

बैठक में मौजूद एक व्यक्ति ने कहा कि चर्चा के कुछ प्रमुख मसलों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) को लुभाने के लिए कदम उठाने, दबाव वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और पिछले कुछ महीनों के विभिन्न संकटों के कारण म्युचुअल फंडों से जुड़े मसले अहम रहे।

सूत्रों ने कहा कि पूंजी बाजारों के हिस्सेदारों ने एलटीसीजी की अलग अलग दरों, प्रतिभूति लेन-देन कर (एसटीटी) और कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (सीटीटी) पर अपने विचार रखे। वरिष्ठ अधिकारियों के एक समूह ने कहा कि कर की दरों को तार्किक बनाया जाना जरूरी है और इससे अनिश्चितता खत्म होगी व निवेशकों की अस्पष्टता की स्थिति से निपटा जा सकेगा।

उपरोक्त उल्लिखित दो व्यक्तियों में से एक ने कहा कि इक्विटी करों से जुड़े कुछ मूल्यांकन और निर्गम के बारे में संबंधित विभागों से जानकारी देने को कहा गया है। स्टॉक एक्सचेंज के एक अधिकारी ने कहा, 'इक्विटी बाजार को विश्वास बहाल करने वाला बूस्टर पैकेज दिए जाने की जरूरत है जिससे निवेशकों को आकर्षित और प्रोत्साहित किया जा सके और वे दीर्घावधि निवेश कर सकें। इससे परंपरागत निवेशक अन्य संपत्ति श्रेणियों में भी निवेश करने को आकर्षित होंगे।'

स्टार्टअप के लिए कुछ करों से राहत की मांग

नेहा अलावधी
नई दिल्ली, 16 दिसंबर

सूचना तकनीक और स्टार्टअप क्षेत्रों ने बजट पूर्व बैठक में आज वित्त मंत्री से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को तार्किक बनाए जाने, एसईजेड में सेवा कंपनियों पर 15 प्रतिशत कॉर्पोरेट कर और कुछ मौजूदा कर दरों से स्टार्टअप को राहत दिए जाने सहित अन्य मांगें रखी हैं।

सूचना तकनीक और बिजनेस प्रॉसेस मैनेजमेंट (आईटी-बीपीएम) उद्योग के संगठन नैशनल एसोसिएशन आफसॉफ्टवेयर ऐंड सर्विसेज कंपनीज (नैस्कॉम) ने कहा कि विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) में नई विनिर्माण कंपनियों पर 15 प्रतिशत कॉर्पोरेट कर लगता है, जिसका विस्तार नई सेवा कंपनियों तक किया जाना चाहिए।

नैस्कॉम ने सरकार को दिए ज्ञापन में कहा है, 'सभी नई विनिर्माण व सेवा कंपनियों पर एसईजेड में 15 प्रतिशत कर की दर होनी चाहिए। इस कदम का बहुत सीमित वित्तीय असर है, लेकिन इससे कंपनियां निवेश के लिए प्रेरित होंगी।'

- बैठक में उद्योग संगठनों, ऐपल, रिलायंस जियो, पेटीएम, उबर सहित अन्य कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल
- विशेष आर्थिक क्षेत्र में नई विनिर्माण कंपनियों पर 15 प्रतिशत कॉर्पोरेट कर लगता है, जिसका विस्तार नई सेवा कंपनियों तक करने की मांग

सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई बैठक में उद्योग संगठनों, ऐपल, रिलायंस जियो, पेटीएम, उबर सहित अन्य कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल रहे, जिन्होंने डिजिटल इकनॉमी, फिनटेक और स्टार्टअप पर अपनी राय दी। यह चर्चा 2 घंटे तक चली।

एसईजेड में कर छूट 31 मार्च 2020 को खत्म होने वाला है और आईटी उद्योग इस नीति का मुख्य लाभार्थी है। सरकार ने एक समिति नियुक्त की है, जो एसईजेड के प्रावधानों पर विचार कर रही है। नैस्कॉम ने जोर दिया है कि ऐसे कदम उठाए जाने की जरूरत है कि एसईजेड जारी रहे, जिससे निवेश आकर्षित हो और यह क्षेत्र निर्यात और रोजगार सृजन में अहम भूमिका निभा सके। इस तरह से एक उचित मामला बनता है कि मौजूदा कर छूट को आगे 5 साल के लिए और बढ़ाया जाए।

उद्योग संगठन ने यह भी कहा है कि सरकार स्टार्टअप में शेयरों की बिक्री के समय इंप्लाई स्टॉक ऑप्शन प्लान (ईएसओपी) के अनुदान में कर देनदारी में छूट दे। नैस्कॉम ने आगे कहा है कि अगले 5 साल के लिए 3,000 करोड़ रुपये का डीप टेक इन्वेस्टमेंट फंड का सृजन किया जाना चाहिए, जो डीप टेक स्टार्टअप के लिए हो।

संगठन ने यह भी कहा है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए कराधान सरल किया जाना चाहिए। साथ ही प्रभावी प्रबंधन की अवधारणा के तहत रिपोर्टिंग व अनुपालन जरूरतें कम की जानी चाहिए।

बैठक में मौजूद रहे इंडियन प्राइवेट इक्विटी ऐंड वेंचर कैपिटल एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत टंडन ने कहा कि वैकल्पिक निवेश कोषों की सेवाओं की जीरो रेटिंग मुहैया कराई जानी चाहिए। आईवीसीए ने कहा कि विदेशी निवेशक के अंशदान में संशोधन के साथ वस्तु एवं सेवा कर कानून के तहत एआईएफ के तहत की गई किसी भी आपूर्ति को डीम्ड एक्सपोर्ट के रूप में अधिसूचित किया जाना चाहिए।

एमईआईएस बहाल करने की वकालत

नेहा अलावधी और शुभायन चक्रवर्ती
नई दिल्ली, 16 दिसंबर

इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी उद्योग मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम (एमईआईएस) दरें मौजूदा 2 प्रतिशत की जगह पूर्ववत बहाल करने की वकालत की है, जिससे भारत से इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्यात को बढ़ावा मिल सके। उद्योग संगठनों और कंपनियों ने आज इस मसले पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से चर्चा की, जिससे उनकी बजट से उम्मीदों के बारे में जाना जा सके।

इंडिया सेलुलर ऐंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (आईसीईए) के चेयरमैन पंकज मोहिंद्रू ने कहा, 'सरकार से हमारा प्रमुख अनुरोध एमईआईएस बहाल करने को लेकर है। यह वैश्विक मूल्य श्रृंखला के लिए बहुत अहम प्रोत्साहन योजना है।'

बजट पूर्व बैठक

बैठक में मौजूद रहे हार्डवेयर उद्योग संगठन एमएआईटी के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी जॉर्ज पॉल ने कहा, 'इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का निर्यात बहुत ज्यादा प्रभावित होगा और इस क्षेत्र में निवेश पर नकारात्मक असर पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात एमईआईएस के बगैर बहुत कठिन हो जाएगा। निर्यात जारी रखने के लिए एमईआईएस बहाल रखना वक्त की मांग है।' विदेश व्यापार नीति के तहत 2015 में पेश मेगा एमईआईएस का सृजन 5 रिवॉर्ड योजनाओं को मिलाकर किया गया था। यह 8,000 से ज्यादा वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहित करता है और अपने तरह की यह सबसे बड़ी योजना है। निर्यातकों को 2 प्रतिशत, 3 प्रतिशत और 5 प्रतिशत नियत दरों के आधार पर ड्यूटी क्रेडिट मिलता है, जो उत्पाद व देश पर निर्भर है।

आईसीईए के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में हैंडसेट का निर्यात 7000 करोड़ पार कर गया, जबकि 2018-19 में कुल निर्यात 11,200 करोड़ रुपये था।

इंटरनेट ऐंड मोबाइल एसोसिएशन आफ इंडिया ने सोमवार को एक बयान में कहा, 'वाणिज्य मंत्रालय द्वारा हाल में एमईआईएस 4 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत किए जाने के मौजूदा दिशानिर्देश नैशनल पॉलिसी आफ इलेक्ट्रॉनिक्स 2019 से तालमेल नहीं खाता, जिसमें 2025 तक हर साल 110 अरब डॉलर के 10 करोड़ हैंडसेट निर्यात का लक्ष्य रखा गया है। मोबाइल हैंडसेट विनिर्माण उद्योग इस मसले पर सरकार के साथ चर्चा कर रहा है और निर्यात प्रोत्साहन बढ़ाकर 8 प्रतिशत करने का इंतजार कर रहा है, जिससे भारत वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बन सके।'

राजमार्ग क्षेत्र में बढ़ रही कर्ज की मांग

मेघा मनचंदा
नई दिल्ली, 16 दिसंबर

राजमार्ग क्षेत्र की सुरंग के आखिर में कुछ रोशनी नजर आने लगी है। देश के प्रमुख बैंकरों का कहना है कि हाल के दिनों में इस क्षेत्र में कर्ज की मांग बढ़ी है और सड़क क्षेत्र में स्थिति में सुधार की राह अब बहुत कठिन नहीं नजर आ रही है।

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के चेयरमैन रजनीश कुमार ने कहा, 'कोई भी कर्ज लेना नहीं चाहता था। अब वे (बुनियादी ढांचा कंपनियां) कर्ज के लिए आवेदन कर रही हैं। उनकी ओर से संकेत मिल रहा है कि उन्हें इस या उस परियोजना के लिए धन की जरूरत है।'

उन्होंने कहा कि सड़क क्षेत्र में कर्ज की मांग बढ़ रही है। स्टेट बैंक से सौर बिजली परियोजनाओं और तेल व गैस क्षेत्र खासकर सिटी गैस परियोजनाओं में भी कर्ज की मांग बढ़ रही है।

विशेषज्ञों का कहना है कि वित्त वर्ष 2019-20 के पहले 4 या 5 महीनों के दौरान कुल मिलाकर मंदी थी, लेकिन अब स्थिति थोड़ी बेहतर नजर आ रही है।

डेलॉयट इंडिया में पार्टनर कुशल कुमार सिंह ने कहा, 'मार्च और अप्रैल में आवंटित परियोजाएं अब फाइनैंशियल क्लोजर की ओर बढ़ रही हैं। हाल के दिनों में कर्ज की मांग बढ़ने में इसकी भी भूमिका हो सकती है।' इसकी अन्य वजह आरओडब्ल्यू (राइट आफ वे) भूमि का कड़ाई से अनुपालन भी हो सकता है।

सिंह ने कहा, 'अब तब तक परियोजनाएं आवंटित नहीं हो सकती हैं, जब तक कि आरओडब्ल्यू के लिए भूमि का अधिग्रहण नहीं हो जाता है।'

इसके पहले प्रमुख एक्सप्रेसवे डेवलपरों व कॉन्ट्रैक्टरों ने शिकायत की थी कि बुनियादी ढांचे की राह में सबसे बड़ी बाधा आरओडब्ल्यू अधिग्रहण थी।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के एक अधिकारी ने कहा, 'हम अपने कार्यक्रम के मुताबिक काम कर रहे हैं। हम अपनी परियोजनाओं का मूल्यांकन और आवंटन समयबद्ध तरीके से कर रहे हैं।'

बहरहाल हर कोई कर्ज की मांग में तेजी को लेकर आश्वस्त नहीं है कि परियोजनाओं में तेजी आ रही है। कुछ का मानना है कि सड़क निर्माण कंपनियों द्वारा अपने कर्ज के पुनर्वित्तपोषण की वजह से ऐसा हो सकता है। उम्मीद की जा रही है कि एनएचएआई अपना ध्यान परियोजनाएं आवंटित करने से आवंटित परियोजनाओं को लागू कराने पर केंद्रित कर सकता है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की हाल की रिपोर्ट के मुताबिक इसकी एक वजह भूमि अधिग्रहण की बढ़ी लागत और उस पर बढ़ता कर्ज है।

रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 20 से वित्त वर्ष 22 के दौरान सड़क परियोजनाओं का आवंटन (हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (एचएएम), बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर (बीओटी) मॉडल और इंजीनियरिंग खरीद निर्माण (ईपीसी) मॉडल पर) घटकर 12,000 से 13,000 किलोमीटर हो सकता है, जो वित्त वर्ष 17 से वित्त वर्ष 19 के बीच औसतन 14,000 किलोमीटर था।

इस साल सितंबर में प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने एनएचएआई को पत्र लिखा था, जिसमें सुझाव दिया गया था कि वह अपने पोर्टफोलियो का पुनर्गठन करे और परियोजनाओं की वाणिज्यिक व्यवहार्यता व संपत्तियो के मुद्रीकरण पर ध्यान केंद्रित करे।

संसद में लिखित जवाब में 28 नवंबर को सड़क मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था, 'अगले तीन महीने में करीब 50,000 करोड़ रुपये की 4,471 किलोमीटर सड़क परियोजनाएं आवंटित करने का लक्ष्य रखा गया है।'

इस साल अप्रैल तक 3,215 किलोमीटर लंबी 168 सड़क परियोजनाओं का आवंटन किया गया है।

धन है अहम

योजना और असल स्थिति

वित्त वर्ष 2020 में एनएचएआई को राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए आवंटित धन और अक्टूबर तक प्राप्तियां

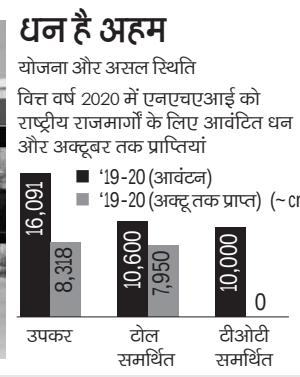

लंबी राह

आवंटित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की कुल लंबाई (किमी में)

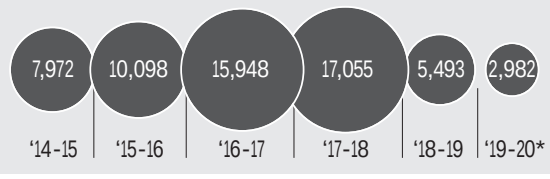

टीओटीः टोल-ऑपरेट-ट्रांसफर *31 अक्टूबर तक

स्रोतः लोकसभा में पूछे गए सवाल

खाद्य महंगाई 71 माह के शीर्ष पर

इंदिवजल धस्माना
नई दिल्ली, 16 दिसंबर

खाद्य महंगाई दर 71 महीने के उच्च स्तर पर पहुंचने के कारण थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) आधारित दरें नवंबर में मामूली बढ़कर 0.58 प्रतिशत पहुंच गई, जो अक्टूबर में 0.16 प्रतिशत थी। खाद्य वस्तुओं में प्याज की महंगाई इस अवधि के दौरान 119.84 प्रतिशत से बढ़कर 172.30 प्रतिशत पर पहुंच गई।

बहरहाल डब्ल्यूपीआई महंगाई दर लगातार तीसरे महीने 1 प्रतिशत से नीचे बनी हुई है, जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित महंगाई दर के विपरीत है। सीपीआई आधारित महंगाई नवंबर महीने में 40 महीने के उच्च स्तर 5.54 प्रतिशत पर पहुंच गई।

ऐसा सिर्फ खाद्य वस्तुओं की वजह से हुआ, जो महंगी हुई हैं। खाद्य वस्तुओं का डब्ल्पीआई में अधिभार 15.26 प्रतिशत है, जबकि सीपीआई में इसका अधिभार 45 प्रतिशत से ज्यादा है।

वहीं गैर खाद्य वस्तुओं की थोक महंगाई घटी है। अर्थव्यवस्था में मंदी और सुस्त मांग की वजह से विनिर्मित वस्तुओं के दाम स्थिर रहे हैं। विनिर्मित वस्तुओं में सिर्फ प्रसंस्कृत खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़े हैं और इनकी महंगाई 3.70 प्रतिशत से बढ़कर 5.05 प्रतिशत हो गई है। ईंधन में गिरावट जारी है।

खाद्य महंगाई दर नवंबर महीने में 71 महीने के उच्च स्तर 11.08 प्रतिशत पर पहुंच गई, जो इसके पहले महीने में 9.80 प्रतिशत थी। इस श्रेणी में सब्जियों की महंगाई 45.32 प्रतिशत बढ़ी है, जो इसके पहले 38.91 प्रतिशत बढ़ी थी।

दलहन ने भी महंगाई बढ़ाई है, जो 16.57 प्रतिशत से बढ़कर नवंबर में 16.59 प्रतिशत पह पहुंच गई। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि इस पर सावधानी से नजर रखने की जरूरत है।

इक्रा में मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नैयर ने कहा, 'सब्जियों के बढ़े दाम समय के साथ उलट जाते हैं, लेकिन दलहन के बढ़े दाम पर सावधानी से नजर रखने की जरूरत है, जब तक कि रबी की बुआई गति नहीं पकड़ लेती।'

खाद्य महंगाई ने अहम भूमिका निभाई है, वहीं प्रमुख महंगाई दर (इसमें विनिर्मित वस्तुएं आती हैं) लगातार नकारात्मक क्षेत्र में बना हुआ है। नवंबर में यह (-) 1.7 प्रतिशत रही।

इंडिया रेटिंग में मुख्य अर्थशास्त्री सुनील कुमार सिन्हा ने कहा, 'खपत की कमजोर मांग के कारण प्रमुख महंगाई दर ऋणात्मक है।'

ताजा आंकड़े

- प्याज की महंगाई ने निभाई अहम भूमिका, **172.3** प्रतिशत महंगी
- कुल मिलाकर महंगाई दर **0.58** प्रतिशत बढ़ी
- प्रमुख महंगाई दर लगातार नकारात्मक क्षेत्र में, नवंबर में यह **-1.7** प्रतिशत रही

बीएस सूडोकू 3614

परिणाम संख्या **3613**

		1			4		3	
			7	9			1	8
				5		6		4
2					6	7		
	4						6	
		7	2					9
7		4		2				
9	1			3	8			
	8		9			4		

2	6	4	9	1	3	7	5	8
3	5	9	2	7	8	1	6	4
1	7	8	4	6	5	3	9	2
8	9	3	5	4	2	6	7	1
7	4	1	6	3	9	8	2	5
5	2	6	1	8	7	9	4	3
9	1	7	8	2	4	5	3	6
4	8	5	3	9	6	2	1	7
6	3	2	7	5	1	4	8	9

कैसे खेलें?

हर रो, कॉलम और 3 बाई 3 के बॉक्स में एक से लेकर नौ तक की संख्या भरें।

बहुत मुश्किल ★★★★★

क्षेत्रीय मंडियों के भाव

उत्तर प्रदेश | राजस्थान | पंजाब

कानपुर
गेहूं लूज 2080/2090, जौ 1770/1780, चावल मसूरी 2250/2300, चावल मोटा 2150/2225, सरसों 4300/4325, तिल सफेद 9400/9600, सोया (टीन) 1500/1525, तेल सरसों कच्ची घानी वैट पेड (टीन)1590/1650,

लखनऊ
गेहूं दड़ा 2100/2125, गेहूं शरबती 2700/2800, चावल शरबती सेला 3700/3750, स्टीम 4200/4300, लालमती 3300/3400, चावल (सोना) 2900/2975,

चंदौसी
(प्रति किलो): मैन्था ऑयल 1449, बोल्ड क्रिस्टल (12 नं.)1535, फ्लैक 1463, डीएमओ 1043, टरपीन लैस बोल्ड 1558

मुजफ्फरनगर
गुड़ (40 किलो): लड्डू 1150/1225, खुरपा 1100/1125, चाकू 1150/1250, रसकट 850/880, शक्कर 1180/1200, चीनी मिल डिली. (क्विं.) (जीएसटी अतिरिक्त): खतौली 3300, सिहोरा 3160, बुंदकी 3180, बुढ़ाना 3250,

हापुड़
गुड़-चीनीः चीनी हाजिर 3550/3600, गुड़ (प्रति 40 किलो) बाल्टी 950/1000, तिलहनः सरसों (42 प्रतिशत कंडी.) 4400, खलः सरसों 2250/2350, बिनौला 2450/2550, चना छिलका 1950/2000,

जयपुर
अनाजः चावल डीबी 5500/5600, गेहूं (मिल) 2145/2150, मक्की 2050/2100, बाजरा 1840/1850, जौ 1800/1825, ग्वार लूज 3750/3800, ज्वार कैटलफीड 2050/2100, तेल-तिलहनः सरसों(मिल पहुंच) 4600/4625,

श्रीगंगानगर
गेहूं (ढेरी) 2050/2100, ग्वार 3800/3825, जौ 2000/2010,

जोधपुर
गेहूं 2050/2080, जौ 1750/1775, पोपकोन मक्की 4400/4500, ग्वार डिलीवरी (ऑलपेड) 4000/4050, ग्वारगम 7500/7600, बाजरा (गुजरात) 1930/1935, बाजरा (जयपुर) 1890/1900, चना 4200/4250, काबली चना 4700/5900, मूंग 6200/6300,

खन्ना
जीएसटी अतिरिक्त (प्रति क्विं.): राइसब्रान (खाद्य)(प्रति प्वाइंट)125, राइसब्रान (अखाद्य) 122, खल सरसों 2000, डीओसीः राइसब्रान बैच सफेद 1250, लाल 1230, कंटीन्यूअस 1290,

लुधियाना
दाल-दलहनः राजमां चित्रा 7000/8000, अरहर दाल 7700/8300, उड़द साबुत 7500/8300, उड़द धोया 9500/10500, छिलका 9000/10000, दाल मसूर 5500/5800, चनादाल 5400/5600,

अमृतसर
चावलः बासमती (1121 नं.) स्टीम 6000/6100, सेला 5500/5600, शरबती साधारण सेला 3700/3800, शरबती स्टीम 4100/4200,चावल 1509 सेला 5100/5200, धानः शरबती 2100/2150,

बठिंडा
रुई (प्रति मन): जे-34 पंजाब नई 3950/4000, हरियाणा 3950/3970, राजस्थान 3900/3980, खल (प्रति क्विं.): बिनौला 2400/2450, सरसों खल 2190/2200,

फाजिल्का
गेहूं 2140/2150, सरसों 4350/4400 रुई (प्रति मन): (जे-34) 3950/4000,कपास देशी 4850/4950, कपास नरमा (क्विं.) 5100/5200, बिनौला (टैक्सपेड): खल 2300/2400,

जालंधर
गेहूं दड़ा 2100/2120, चावल परमल कच्चा 2450/2500, से ला 2375/2400, मक्की यूपी 2300/2310, बिहार 2365/2370, दाल उड़द छिलका 8700/10500, चना देशी 4975/5050, दाल चना 5100/5350, काबली चना 4800/5700, राजमां चित्रा पुणे 6700/8000, चीन 7000/7600,

करनाल
गेहूं दड़ा 2130/2140, बासमती चावल 6400/6500, धान 1121 नं. 2800/2850, पूसा 1509 धान 2500/2575, शरबती धान 2150/2200, सेला (1509 नं.) चावल 5100/5150, स्टीम 5800/5900,

हिसार
ग्वार 3750/3800, जौ 1775/1780, सरसों 4200/4215, मूंग 6500/6600, गेहूं 2140/2150,

जींद
जीएसटी अतिरिक्तः गेहूं 2100/2150, आटा (प्रति 44 किलो) 1070/1090, मैदा 1175/1190, देशी घी (एक ली/जार) 370/470, रिफाइंड (टीन) 1385/1400,

भिवानी
जीएसटी अतिरिक्तः सरसों 4250/4300, खल बिनौला मोटी 2300/2500, बिनौला 2800/3200, सरसों तेल 9050/9100, गेहूं 2100/2200, ग्वार 3750/3800, बाजरा 1800/1850 *एनएनएस*

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 258

नई दिल्ली का पुनर्निर्माण

केंद्र सरकार मध्य दिल्ली के व्यापक पुनर्निर्माण की जिस योजना पर काम कर रही है उस पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यह वह इलाका है जहां सरकार के कार्यालय और ऐतिहासिक महत्त्व वाला केंद्रीय सचिवालय तथा संसद भवन स्थित हैं। योजना की कुछ सरसरी जानकारी है: उदाहरण के लिए राजपथ पर इंडिया गेट और विजय चौक के दोनों ओर स्थित समाजवादी दौर की इमारतों को तोड़ा जा सकता है या उनका पुनर्निर्माण किया जाएगा। यह भी संभव है कि मौजूदा संसद और केंद्रीय सचिवालय समेत अंग्रेजी युग की कुछ इमारतों को संग्रहालय बना दिया जाए और वहां होने वाले कामकाज नये भवनों में हों। परंतु कुल मिलाकर इस पुनर्निर्माण के दायरे और इससे जुड़ी बातों को अनावश्यक रूप से अस्पष्ट रखा जा रहा है। एक बात जो पता है वह यह कि इसके डिजाइन में 'नये भारत के मूल्यों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व' होना चाहिए और इसमें 'भारतीय संस्कृति और सामाजिक परिवेश' समाहित होना चाहिए। ये बातें भी अस्पष्ट सी हैं। नई इमारतों की जीवनावधि भी पहले 150 और उसके बाद 250 वर्ष बताई गई।

अक्टूबर में कई फर्मों ने इस परियोजना के लिए निविदा प्रस्तुत की। इसकी लागत ज्ञात नहीं है लेकिन अनुमान है कि यह राशि 12,000 करोड़ रुपये से 25,000 करोड़ रुपये के बीच हो सकती है। यह बोली एचसीपी डिजाइन, प्लानिंग ऐंड मैनेजमेंट कंपनी को हासिल हुई। अहमदाबाद की यह कंपनी साबरमती रिवर फ्रंट के विकास कार्य से जुड़ी रही है। यह वही परियोजना है जिसका जिक्र तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर किया करते थे। यह भी ज्ञात नहीं है कि इसका चयन कैसे किया गया और इसके मानक क्या थे? इस डिजाइन में मौजूदा केंद्रीय सचिवालय और राष्ट्रपति भवन के बीच प्रधानमंत्री के लिए एक विशाल नया आवास बनाना शामिल है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और उस संवैधानिक मान्यता के प्रतिकूल है जिसके तहत प्रधानमंत्री को कैबिनेट के समकक्षों में प्रथम माना जाता है। इंडिया गेट के षटकोणीय इलाके में स्थित ऐतिहासिक आवासों का क्या होगा यह अभी स्पष्ट नहीं है क्योंकि एचसीपी की बोली के बारे में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी बताती है कि इनमें से कुछ आवास सचिवालय के सहायक कार्यालय बनेंगे। अनुमान है कि यह पुनर्निर्माण कार्य 2024 तक पूरा हो जाएगा। संयोग की बात है कि लगभग उसी समय देश में अगले आम चुनाव होंगे।

इस परियोजना पर कड़ी निगरानी रखने की आवश्यकता है। यदि इसे सदियों तक बरकरार रखने लायक बनाना है तो ऐसा नहीं हो सकता कि इसके डिजाइन को गोपनीय रखा जाए और पांच साल से कम वर्ष में इसका निर्माण कर लिया जाए। इस बोली के बारे में वास्तुविदों, संरक्षणवादियों और विरासत के विशेषज्ञों की क्या राय रही? इन मशविरों को सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? भारतीय गणराज्य का सर्वाधिक पवित्र सार्वजनिक स्थल होने के बावजूद इसके बदलाव की योजना पर राष्ट्रीय बहस क्यों नहीं हुई? शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी यदि नहीं चाहते कि आने वाले दशकों में उनके कार्यकाल को हड़बड़ी में किए गए इस विकास कार्य के लिए जाना जाए तो उन्हें पारदर्शिता और मशविरा बढ़ाना चाहिए। सबसे अहम बात, इस पुनर्निर्माण कार्य के अन्य प्रभावों पर गौर किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए माना जा रहा है कि नई संसद में ज्यादा लोक सभा सदस्यों की बैठक व्यवस्था होगी। क्या कुछ वर्ष बाद होने वाले परिसीमन के बाद हिंदी प्रदेशों के सांसदों की तादाद बढ़ सकती है जबकि आबादी पर नियंत्रण रखने वाले अन्य राज्यों में उतने ही सांसद रहेंगे? यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्या इस बदलाव को लेकर इतनी गोपनीयता बरते जाने की यह भी एक वजह है?

अजय मोहंती

देश की अर्थव्यवस्था का पतन हो रहा है?

क्या देश की अर्थव्यवस्था में तेजी से गिरावट आ रही है और क्या इसे उबारने के लिए हमें नये तौर तरीके अपनाने होंगे? इन सवालों के जवाब दे रहे हैं अजित बालकृष्णन

कोई भी समाचार पत्र या वेबसाइट खोलकर देखिए, बुरी खबरों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ऐसा लगता है जैसे एक के बाद एक उद्योग धंधे धराशायी हो रहे हैं। यात्री कार निर्माता, दूरसंचार सेवा प्रदाता, विमानन कंपनियां, छोटे कारोबारों को कर्ज देने वाले बैंक, अचल संपत्ति कारोबारी, विनिर्माण कंपनियां, टेलीविजन प्रसारक और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की बड़ी निर्यातक कंपनियां तक संकट का सामना कर रही हैं। खबरों की सुर्खियां देखें तो लगता है कि अर्थव्यवस्था के तमाम संकेतक नकारात्मक दिशा में बढ़ रहे हैं। फिर चाहे सकल घरेलू उत्पाद हो, रोजगार दर हो या डॉलर के मुकाबले रुपया हो।

लेखक और स्तंभकार अपने राजनीतिक झुकाव के आधार पर यह तय करते हैं कि इस गिरावट के लिए किसे उत्तरदायी ठहराना है: भ्रष्ट कारोबारियों को, मोदी सरकार बिना सोचे विचारे उठाए गए आधुनिकीकृत कदमों मसलन नोटबंदी, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) और इलेक्ट्रिक कार पर जोर देने को या हताश वित्त मंत्री द्वारा देश के कारोबारियों पर अकल्पनीय रूप से गलत कर लगाने को, दुनिया पर दबदबा कायम करने की चीन की महत्त्वाकांक्षा को या डॉनल्ड ट्रंप और अमेरिका के नये संरक्षणवादी रुख को।

इस हताश करने वाले माहौल के लिए जो हल सुझाए जा रहे हैं वे इस प्रकार हैं: बैंक ब्याज दरों में कमी करना, मुद्रास्फीति में कमी लाना और घाटे में चल रहे सरकारी उपक्रमों को बेचना। ये सारे उपाय सन 1960 के दशक के लता मंगेशकर तथा मोहम्मद रफी द्वारा गाये युगल गीत की याद दिलाते हैं।

यहां हमें रुककर इस बात पर विचार करना होगा कि क्या इन गिरावट वाले रुझानों में कहीं कोई अंत:संबंध हैं।

क्या कार पार्किंग की जगह की कमी और शहरों में अत्यधिक भीड़भाड़ वाले मार्गों की वजह से बड़ी तादाद में लोगों ने कार खरीदना कम कर दिया है? क्या इसकी वजह से कारों की बिक्री में कमी आ रही है और कार निर्माता तथा उनके कलपुर्जों का उत्पादन करने वाली कंपनियां उत्पादन कम कर रही हैं और लोगों को काम से हटा रही हैं? क्या इसकी वजह से ही कार डीलरों, पेट्रोल पंप, मरम्मत करने वालों और कार के लिए ऋण देने वाली कंपनियों का कामकाज प्रभावित हो रहा है। क्या इन तमाम वजहों से देश में ऋण का प्रमुख माध्यम मानी जाने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की हालत इतनी खस्ता है और पूरे देश में कारोबार लड़खड़ाया हुआ है? यदि यह आंशिक रूप से भी सच है तो क्या हमें नेटवर्क इकनॉमिक्स के उपकरणों का इस्तेमाल करके यह पता लगाने का प्रयास करना चाहिए कि समस्या की जड़ें दरअसल कहां निहित हैं? या फिर क्या संभव है कि मांग और रोजगार की अगली तेजी सेवा क्षेत्र में आएगी? क्या नई तकनीक चिकित्सकों, विधिक शुल्क, बीमा आदि की कीमतों में इतनी कमी लाएगी कि वह शायद मौजूदा मूल्य के 10वें हिस्से के बराबर हो जाए? उदाहरण के लिए क्या किसी सामान्य चिकित्सक के पास आम चिकित्सा जांच 10 रुपये में कराई जा सकती है जिसके लिए आज 600 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। और क्या किसी रिक्शा चालक के पूरे परिवार के लिए संपूर्ण चिकित्सा बीमा बिना किसी सरकारी सब्सिडी के 100 रुपये वार्षिक की दर पर हासिल किया जा सकता है।

तकनीक में यह क्षमता है कि वह इन सेवाओं की मांग में कई गुना इजाफा कर सके। जैसा कि जेम्स बेसेन ने जनवरी 2018 में प्रकाशित राष्ट्रीय आर्थिक शोध ब्यूरो के पर्चा क्रमांक 24,235 में लिखा है, 'पहले के युग में, कपास के वस्त्र की खपत बढ़ी। ऐसा सन 1814 में अमेरिकी टेक्सटाइल यूनिटों में पावर लूम के आगमन के बाद हुआ, स्टील की खपत में तब इजाफा हुआ जब 1856 में अमेरिका में बेसमेर स्टील निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हुई, जबकि सन 1913 में हेनरी फोर्ड द्वारा असेंबली लाइन शुरू करने के बाद मोटर वाहनों के निर्माण में तेजी आई।'

ऐसा करने के लिए हमें नवाचार को लेकर देश के रुख पर नए सिरे से नजर डालनी होगी। अमेरिका जैसे पूंजीवादी देश में भी नवाचार सरकार समर्थित पहल से आता है। इसे गोपनीय रखा जाता है और अमेरिकी मीडिया व्यक्तिगत तौर पर उद्यमियों को नायक के रूप में पेश करता है। मारियाना मज्जुकाटो की पुस्तक द आंत्रेप्रेन्योरियल स्टेट में राह रोकने वाली अफसरशाही व्यवस्था बनाम जीवंत निजी क्षेत्र के मिथक को खत्म करती हैं। आईटी से लेकर बायोटेक्नॉलजी तक केस स्टडीज के एक पूरे सिलसिले में वह दिखाती हैं कि निजी क्षेत्र केवल तभी निवेश का साहस दिखाता है जब सरकारी क्षेत्र इसमें भी अक्सर रक्षा क्षेत्र उच्च जोखिम वाला निवेश करता है। वह एक अध्याय में बताते हैं कि कैसे आईफोन को स्मार्ट बनाने वाली की तकनीक अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा फंड की गई और निजी कंपनी द्वारा उसे अंजाम दिया गया। भारत इस क्षेत्र में बुरी तरह नाकाम है। रक्षा क्षेत्र की फंडिंग सरकारी शोध संस्थानों के माध्यम से होती है जहां वैज्ञानिक अफसरशाहों की तरह बैठक करते हैं और प्रेस विज्ञप्तियां जारी करते हैं। नवाचार तो काफी पहले बंद हो चुका है। जब तक इस दिक्कत को दूर नहीं किया जाता, भारत के नए उद्योगों में रोजगार पैदा करने और दुनिया में अग्रणी होने की संभावना कम है।

असल बात यह है कि भारत के लिए वक्त आ गया है कि वह नई औद्योगिक नीति तैयार करे जो पूरी तरह सरकारी या निजी के बजाय बीच का कोई समझदारी भरा रास्ता अपनाए। फ्रेड ब्लॉक का 2008 का पर्चा स्विमिंग अगेंस्ट द करेंट: द राइज ऑफ द हिडेन डेवलपमेंट स्टेट इन द यूनाइटेड स्टेट्स में इस बारे में बात करता है और कहता है कि हमें आर्थिक नीति के लिए ऐसा एजेंडा बनाना होगा जो बीच का समझदारी भरा रास्ता अपनाए। औद्योगिक नीति में बदलाव की इस आवश्यकता को अतीत के उन दिनों को वापस लाने की बात नहीं समझा जाना चाहिए जब अर्थव्यवस्था पर राज्य का दबदबा था। बल्कि कहने का अर्थ यह है कि तेज तकनीकी बदलाव एक हकीकत है और कारोबारी अर्थव्यवस्था में इस बदलाव को बढ़ावा देने में सरकार की अहम भूमिका होनी चाहिए। जैसा कि ब्लॉक कहते हैं इसके लिए ऐसी औद्योगिक नीति चाहिए जहां सरकारी अधिकारी तकनीकविदों से मशविरा करें और तकनीकी चुनौतियों का पता लगाएं। इसका निस्तारण पूरी तरह नए उद्योगों को सामने लाएगा। ब्याज दरों के साथ छेड़छाड़, मुद्रास्फीति को निशाना बनाने या सब्सिडी से कोई कोई सहायता नहीं मिलने वाली।

जलवायु परिवर्तन की दर दुरुस्त करने की पहल

जमीनी हकीकत

सुनीता नारायण

जलवायु परिवर्तन पर चर्चा का एक और दौर मैड्रिड में संपन्न हुआ है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (सीओपी-25) कुछ मामलों में अलग है। इस बार लगभग आम-सहमति बनी है कि जलवायु परिवर्तन वास्तव में हो रहा है। अब हर कोई यह मानता है कि इस दिशा में काम करने का वक्त हो गया है। अब और हीलाहवाली नहीं चलेगी। तथ्य यह है कि मैड्रिड में कदमों को गलत ठहराने या नाममात्र एवं सस्ते कदम उठाने के तरीके तलाशने को लेकर नए खेल खेले गए। सीओपी-25 सम्मेलन में विश्वसनीय बाजार प्रणाली के विकास को लेकर काफी चर्चा हुई। देशों को कार्बन-तटस्थ या विशुद्ध रूप से शून्य-कार्बन वाला बनाने के लिए ऐसी बाजार प्रणालियां बेहद जरूरी हैं।

यह सब सुनने में काफी अच्छा और बड़ा लग रहा है। लेकिन कहते हैं न कि प्याले से मुंह तक पहुंचने में बहुत कुछ हो सकता है। जलवायु संबंधी वार्ताओं में मैंने यह पाया है कि अक्सर सराहनीय विचार पेचीदा बहसों तक ही सीमित होकर रह जाते हैं। असल में यह रोजमर्रा का काम है। इसका पता आपको तब चलता है जब गुबार थम चुका होता है।

मसलन, वर्ष 2015 में पेरिस में संपन्न सीओपी-21 की घटनाओं को लीजिए। उस समय मनोदशा उत्साह से भरपूर थी क्योंकि एक नया समझौता हुआ था। सभी देशों ने उत्सर्जन में कटौती संबंधी प्रतिबद्धता पर सहमति जताई थी। राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अंशदान (एनडीसी) कहे जाने वाले इन लक्ष्यों तक काफी चर्चा के बाद पहुंचा जा सका था। यह भी तय किया गया था कि एनडीसी का मकसद धरती का तापमान पूर्व-औद्योगिक काल से 1.5 डिग्री सेल्सियस वृद्धि के खतरनाक स्तर से नीचे ही रखना है। लेकिन अब पेरिस की 'सफलता' के भेद खुल रहे हैं।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2019 में कहा गया है कि अगर सभी देश एनडीसी में दर्ज कदमों पर चलते हैं तो वर्ष 2100 तक वैश्विक तापमान में 3.2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाएगी। इतना ही नहीं, देश खासकर कार्बन बजट का बेजा इस्तेमाल कर चुके अमीर देश उतना भी नहीं कर रहे हैं जिनके लिए वे हामी भर चुके हैं। मसलन, जर्मनी स्थित संगठन क्लाइमेट ट्रैकर के मुताबिक, अमेरिका, रूस और सऊदी अरब के कदम 4 डिग्री सेल्सियस, चीन एवं जापान के कदम 3-4 डिग्री सेल्सियस और यूरोपीय संघ के भी कदम 2-3 डिग्री सेल्सियस वृद्धि का सबब बनते हैं। इसका मतलब है कि अगर सभी देशों ने उत्सर्जन के इसी स्तर का अनुसरण किया तो इस सदी के अंत तक तापमान 2-4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। अब हकीकत पर लौटते हैं। ग्रीनहाउस गैस के उत्सर्जन पर काबू पाने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए जा रहे हैं और ऐसा तब हो रहा है जब करोड़ों लोगों को बुनियादी ऊर्जा सुरक्षा मिलने का अब भी इंतजार है।

इस हकीकत के बीच विशुद्ध शून्य कार्बन का विचार सुनने में काफी अच्छा लगता है। इसका यह मतलब है कि देश अपने लक्ष्य से नीचे रह जाएंगे। यानी वे ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन करते रहेंगे लेकिन वे कार्बन के अवशोषण या निपटाने के तरीके निकालेंगे ताकि उनके बही-खाते में उत्सर्जन शुद्ध-शून्य नजर आए। लिहाजा इस कार्बन का अवशोषण कैसे काम करता है? एक, उत्सर्जन योग पेड़ों में मौजूद कार्बन डाई-ऑक्साइड की गणना करेगा कि कितना उत्सर्जन हुआ और कितना अवशोषित हुआ।

फिर ऐसी नई तकनीकें भी हैं जो वातावरण से कई टन कार्बन डाई-ऑक्साइड सोखने और उसे जमीन के भीतर दफनाने का काम करेंगी। इसका यह मतलब होगा कि देश अब न केवल उत्सर्जन में कटौती करने बल्कि प्रसार जारी रखने और फिर सबकी सफाई की योजना बना सकता है। वे दूसरे देशों में कार्बन-अनुकूल परियोजनाओं में निवेश कर क्रेडिट भी खरीद सकते हैं और उसे अपने बही-खाते में उसे जोड़ सकते हैं।

यहां पर बाजारों को लेकर चर्चा भी महत्त्वपूर्ण हो जाती है। यह भी एक तथ्य है कि अफ्रीका या एशिया के सुदूर गांवों में पेड़ लगाना यूरोप या जापान में पेड़ लगाने से कहीं अधिक सस्ता है। हमारी दुनिया में अब भी उत्सर्जन कटौती के सस्ते विकल्प मौजूद हैं। लिहाजा बाजारों को इस तरह डिजाइन किया जा रहा है कि कार्बन धमक एवं क्रेडिट के लिए विकासशील देशों में निवेश किया जा सकता है। इन जलवायु परिदृश्यों में काम कर चुके हम जैसे अधिकतर लोगों के लिए ये शब्दावलियां जानी-पहचानी हैं।

वर्ष 1997 के क्योटो समझौते में क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म विकासशील देशों में तकनीकी संक्रमण के लिए भुगतान करने के ऐसे ही विचार से शुरू हुआ था लेकिन जल्द ही यह सस्ता एवं पेचीदा होते हुए भ्रष्ट विकास व्यवस्था में तब्दील होता चला गया। पेरिस समझौते के बाद इस बार सभी देशों को घरेलू स्तर पर उत्सर्जन कटौती करनी है। इसलिए अगर भारत अपना सस्ता उत्सर्जन कटौती विकल्प किसी अमीर देश को बेच देता है तो वह उस कटौती स्तर को कैसे हासिल कर पाएगा जिसकी जरूरत इस दुनिया को है? याद रखें कि अमीर एवं गरीब दोनों के लिए ही यह एक बड़ा संकट है क्योंकि तापमान वृद्धि का असर सब पर एक जैसा होगा। सवाल है कि क्या किया जाना चाहिए? शुद्ध-शून्य लक्ष्य तय करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन इसका उद्देश्य देशों को घरेलू स्तर पर अधिक कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करना और फिर जो कुछ भी बचा हुआ है उसे वैश्विक लेनदेन प्रणालियों के जरिये खरीदने का होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब कार्बन बिक्री पर एक आधार मूल्य तय करना है, इस दर से नीचे परियोजनाएं योग्य नहीं हो पाएंगी।

इसका यह मतलब होगा कि विकासशील देशों में केवल उन्हीं परियोजनाओं को फंड मिलेगा जो कायापलट करने वाली हैं। भारत जैसा देश अधिक स्वच्छ भविष्य की तरफ छलांग लगा सकता है। हम पहले प्रदूषण फैलाने और फिर उसकी साफ-सफाई से बच सकते हैं। हम इसी भविष्य की चाह रखते हैं। लेकिन ऐसा होने के लिए जलवायु समझौतों के शब्दों पर अमल करना होगा, केवल बात करने से काम नहीं चलेगा।

(लेखिका सेंटर फॉर साइंस ऐंड एनवायरनमेंट से संबद्ध हैं)

कानाफूसी

अल्पसंख्यकों की मदद

उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की सरकार जम्मू कश्मीर तथा पूर्वोत्तर के उन छात्रों की सहायता के लिए कदम उठा रही है जो प्रदेश में पढ़ाई कर रहे हैं और जिन्हें अनुच्छेद 370 के कुछ प्रावधान हटाये जाने और नागरिकता संशोधन अधिनियम पारित होने के बाद दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सितंबर 2019 में उन्होंने अपने आधिकारिक आवास पर जम्मू कश्मीर के करीब 80 छात्रों से मुलाकात की थी और मदद का आश्वासन दिया था। इस बैठक के बाद एक समिति का गठन किया गया था। अब राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने राज्य भर से ऐसे छात्रों के नामांकन के आंकड़े जुटाने शुरू किए हैं ताकि उनकी मदद का खाका तैयार किया जा सके। सूत्रों के अनुसार इसमें वित्तीय मदद भी शामिल है।

अच्छा प्याज बनाम बुरा प्याज

तमिलनाडु के सहकारिता मंत्री सेल्लुर के राजू अक्सर अपने विचारों के लिए सोशल मीडिया पर ट्रोल के शिकार होते रहते हैं। मिसाल के तौर पर एक बार वह कह चुके हैं कि पानी को वाष्प बनने से रोकने के लिए जलाशयों को थर्मोकोल की शीट से ढक देना चाहिए। इन दिनों वह प्याज पर की गई टिप्पणियों के लिए फिर चर्चा में हैं। केंद्र सरकार ने प्याज की कमी से निपटने के लिए इजिप्ट से आयात करने का निर्णय लिया तो ऐसी खबरें आईं कि आयातित प्याज स्वाद में मीठा है और वह स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदेह है। राजू ने इन अफवाहों के खंडन के लिए संवाददाता सम्मेलन बुलाया। उन्होंने कहा कि आयातित प्याज में सल्फर की मात्रा अधिक है जो प्याज को तीखा बनाता है और हृदय के लिए भी बेहतर है। मुख्यमंत्री एडापड्डी पलनिस्वामी ने आयातित प्याज को काटा और लोगों के सामने चखने के बाद अधिकारियों से कहा कि वे इसे पत्रकारों को भी खिलाएं ताकि उन्हें सच्चाई पता लग सके। इसके बाद तो सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ ही आ गयी।

आपका पक्ष

नागरिकता संशोधन कानून का विरोध

देश के पूर्वोत्तर राज्य असम में नागरिकता संशोधन विधेयक का विरोध संसद से कानून बनने से पहले किया जाने लगा था। इस विधेयक के संसद से पारित होने तथा कानून बनने के बाद असम में विरोध प्रदर्शन हिंसात्मक हो गया। विरोध प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक संपत्तियों को जलाया गया। विरोध प्रदर्शन धीरे-धीरे अन्य राज्यों में फैलने लगा। नागरिकता संशोधन कानून में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के शिकार हुए गैर मुस्लिम धर्म को भारत में नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। इस कानून का कथित बुद्धिजीवियों द्वारा विरोध करना समझ से परे है। ऐसा लगता है कि विपक्षी दल इस कानून का विरोध कर सरकार को घेरने की योजना बना रहे हैं। संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर कहा कि भारत में रह रहे किसी भी धर्म के व्यक्ति को इस नए कानून से कोई नुकसान नहीं होने वाला है। भारत में जो भी रह रहा है, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, वह भारत का नागरिक है और आगे भी रहेगा। बहरहाल विरोध की आग दिल्ली में पहुंची और जामिया विश्वविद्यालय के छात्रों ने कई बसें जला दीं। विरोध प्रदर्शन में हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। विरोध की आड़ में हिंसा करने वाले अराजक तत्त्वों पर कड़ाई से कार्रवाई करने की जरूरत है जिससे आम लोगों तथा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान होने से बचाया जा सके और शांति कायम की जा सके।

मोहित कुमार, नई दिल्ली

रविवार को प्रदर्शन के दौरान जामिया विश्वविद्यालय के पास डीटीसी बसों को जलाया गया

दवाओं के दुष्प्रभाव भी होते हैं

आधुनिक विज्ञान ने अगर मनुष्य को बड़ी से बड़ी बीमारियों से बचाने के लिए कई तरह की दवाइयां और तकनीक विकसित की है, लेकिन छोटी-छोटी बीमारियों से निजात दिलाने के लिए जो दवाइयां बनाई गई हैं वे सेहत पर दुष्प्रभाव भी जरूर डालती होंगी। एंटीबायोटिक दवाई के अत्यधिक इस्तेमाल से लोगों की जिंदगी को खतरा भी है। दुनिया के दूसरे देशों में देसी इलाज के साधन नहीं हैं। इसलिए वहां एंटीबायोटिक दवा का अत्यधिक प्रयोग होना स्वाभाविक है। ऐसे देश भारत से देसी इलाज के गुर लेकर अपने नागरिकों को एंटीबायोटिक दवा का अनावश्यक इस्तेमाल होने से बचा सकते हैं। हमारे देश के लोगों ने खुद और अपने बच्चों को भी सर्दी, खांसी और जुकाम जैसी छोटी-छोटी बीमारियों से निजात दिलाने के लिए एंटीबायोटिक दवाओं पर निर्भर कर लिया है। सरकार को इसे गंभीरता से लेते हुए छोटी-छोटी बीमारियों के इलाज से छुटकारा पाने के लिए एंटीबायोटिक का प्रयोग नहीं करने और अपना डॉक्टर खुद नहीं बनने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाने चाहिए। अक्सर यह भी देखा जाता है कि कुछ लोग स्वयं डॉक्टर बनकर दवाइयों का सेवन करने लगते हैं। ऐसा करना खुद के लिए हानिकारक भी साबित हो सकता है। छोटी-छोटी बीमारियों या दर्द के लिए घरेलू आयुर्वेदिक नुस्खे अपनाए जा सकते हैं क्योंकि इनसे शरीर पर कोई दुष्प्रभाव होने की संभावना बहुत कम होती है। देश की आबादी का बहुत बड़ा भाग अशिक्षित है या फिर दवाइयों की असली या नकली की पहचान करने में असमर्थ है। इसलिए घटिया दवाओं पर नकेल कसने के लिए सरकार और प्रशासन को कारगर कदम उठाने चाहिए।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

प्याज के भाव 13 फीसदी बढ़े

दिलीप कुमार झा
मुंबई, 16 दिसंबर

किसानों की सीमित आपूर्ति के कारण अपरिपक्व प्याज की आवक की रफ्तार में कमी आने के बाद प्याज के दाम एक बार फिर उछलकर इस सत्र के शीर्ष स्तर तक पहुंच गए हैं। बेंचमार्क लासलगांव की कृषि उपज विपणन समिति (एपीएमसी) में 3 दिसंबर को प्याज के दाम प्रति किलोग्राम 75 रुपये (आदर्श मूल्य) के स्तर तक पहुंचने के बाद 9 दिसंबर को गिरकर प्रति किलोग्राम 47 रुपये हो गए थे। चालू सत्र की अधपकी फसल आपूर्ति बढ़ने के कारण ऐसा हुआ था। हालांकि फिर से लगातार बढ़ते हुए प्याज के दाम शुक्रवार को 73 रुपये प्रति किलोग्राम हो गए और सोमवार को दाम 13 प्रतिशत बढ़कर 86 रुपये प्रति किलोग्राम हो गए। शनिवार और रविवार को मंडी अधिकारिक रूप से बंद रही। देश भर में खुदरा में प्याज 120 से 140 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर बिक रहा है।

रणनीति में बदलाव करते हुए किसानों ने लाल प्याज की कटाई धीमी कर दी है ताकि लंबे समय तक ज्यादा दाम प्राप्त किए जा सकें। चूंकि सरकार ने स्टॉकिस्टों और खुदरा विक्रेताओं के लिए स्टॉक सीमा लागू की हुई है, इसलिए किसानों ने फसल कटाई का सत्र लंबा खींचने के लिए आपूर्ति कम कर दी है। तब तक खरीफ सत्र के आखिर वाली आवक बाजार में आनी शुरू हो जाएगी।

लासलगांव एपीएमसी के सचिव नरेंद्र वाधवाने ने कहा कि लासलगांव मंडी में प्याज की आवक में तीव्र गिरावट आई है। दूसरी तरफ देश भर से मांग का दबाव बना है जिसने प्याज के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचाने में मदद की है। प्याज के दाम निकट भविष्य में कम होने के आसार हैं, लेकिन फिर भी कम से कम खरीफ सत्र के अंत वाली फसल आनी शुरू होने तक दाम कुछ और समय तक तेज रहेंगे। सोमवार को लासलगांव मंडी में प्याज की कुल आवक केवल 450 टन दर्ज की गई, जबकि शुक्रवार को आवक 1,215 टन थी। लासलगांव एपीएमसी में 3 दिसंबर को प्याज आवक 460 टन दर्ज की गई थी। निफाड (लासलगांव) के आशीष दाभले ने कहा कि किसानों को यह बात पता है कि देश के प्रमुख प्याज उत्पादक राज्य महाराष्ट्र में करीब 30 प्रतिशत फसल को नुकसान पहुंचा है। इस वजह से उन्होंने लाल प्याज की कटाई धीमी कर दी है। चूंकि अधिक नमी की वजह से काटा गया यह प्याज दो दिन में ही खराब हो जाता है, इसलिए इसे कुछेक दिन के बाद स्टोर करके नहीं रखा जा सकता है। अगर किसान इसकी तेजी से कटाई करेंगे तो इसके दामों में गिरावट आने लगेगी। सरकार द्वारा स्टॉक सीमा लागू किए जाने से किसानों और स्टॉकिस्टों पर अपनी उपज जल्दी बेचने का दबाव बना है। इस कारण किसानों ने आपूर्ति सीमित करने के लिए अपनी फसल कटाई कम कर दी है।

सरकार ने इस साल नवंबर में थोक और खुदरा विक्रेताओं के लिए स्टॉक सीमा क्रमशः 50 टन और 10 टन कर दी थी जिसे बाद में घटाकर 25 और पांच टन कर दिया गया। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने 10 दिसंबर को खुदरा विक्रेताओं के लिए स्टॉक सीमा और कम करके इसे केवल दो टन कर दिया था।

लासलगांव में भाव (रुपये प्रति क्विंटल)

दिन	कीमत	दिन	कीमत
2 जनवरी	701	15 जुलाई	1,201
14 जनवरी	580	2 अगस्त	1,320
2 फरवरी	480	16 अगस्त	1,870
15 फरवरी	401	5 सितंबर	2,450
2 मार्च	425	17 सितंबर	3,301
15 मार्च	581	1 अक्टूबर	3,200
2 अप्रैल	851	16 अक्टूबर	2,700
16 अप्रैल	871	2 नवंबर	4,901
3 मई	801	15 नवंबर	3,511
14 मई	901	2 दिसंबर	6,501
1 जून	1,200	3 दिसंबर	7,501
15 जून	1,260	13 दिसंबर	7,300
1 जुलाई	1,360	16 दिसंबर	8,600

स्रोत- एनएचआरडीएफ, संकलन- बीएस रिसर्च

एल्युमीनियम आयात शुल्क में कटौती की मांग

उत्पादन लागत, उलट शुल्क संरचना और आयात बढ़ने से झेलनी पड़ रही है परेशानी

जयजित दास
भुवनेश्वर, 16 दिसंबर

- एल्युमीनियम विनिर्माताओं की प्रमुख कच्चे माल पर आयात शुल्क में कटौती के जरिये शुल्क संरचना की विसंगतियां दूर करने की मांग
- विनिर्माताओं ने केंद्र सरकार से वित्त वर्ष 2021 के बजट से पहले आवश्यक सामग्री पर शुल्क में कमी करने का अनुरोध किया

बढ़ते आयात और धातु उत्पादन लागत में इजाफे से परेशान एल्युमीनियम विनिर्माताओं ने प्रमुख कच्चे माल पर आयात शुल्क में कटौती के जरिये शुल्क संरचना की विसंगतियां दूर करने की मांग की है। चूंकि प्रमुख कच्चे माल पर भारी आयात शुल्क की वजह से एल्युमीनियम के तैयार उत्पाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी प्रतिस्पर्धी क्षमता गंवा रहे हैं, इसलिए एल्युमीनिमय विनिर्माताओं ने केंद्र सरकार से वित्त वर्ष 21 के बजट से पहले आवश्यक सामग्री पर शुल्क में कमी करने का अनुरोध किया है।

एल्युमीनियम कंपनियों ने भारतीय एल्युमीनियम संघ (एएआई) के माध्यम से बात रखते हुए चार प्रमुख कच्चे माल – कैलसाइन्ड पेट्रोलियम (सीपी) कोक, कास्टिक सोडा लाई, एल्युमीनियम फ्लोराइड और ग्रीन एनोड पर आयात शुल्क घटाकर 2.5 प्रतिशत करने की मांग की है। इस कच्चे माल पर मौजूदा शुल्क 7.5 से 10 प्रतिशत के दायरे में है।

उद्योग के एक सूत्र ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारत के तैयार उत्पाद ज्यादा महंगे और गैर-प्रतिस्पर्धी हैं। परिणामस्वरूप तैयार उत्पादों के सस्ते आयात के मुकाबले असुरक्षा उत्पन्न हो रही है और देश में मूल्य संवर्धन हतोत्साहित हो रहा है। एल्युमीनियम उद्योग की लागत संरचना में सुधार करने और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए प्रमुख कच्चे माल पर मूल सीमा शुल्क कम करना जरूरी है।

भारतीय एल्युमीनियम उद्योग उलट शुल्क संरचना से भी परेशान है। जहां कैलसाइन्ड पेट्रोलियम कोक आयात पर 10 प्रतिशत शुल्क लगता है, वहीं एल्युमीनियम के तैयार उत्पादों पर 7.5 प्रतिशत शुल्क लगता है। इसी तरह कास्टिक सोडा लाई पर आयात शुल्क 7.5 प्रतिशत है, जबकि एल्युमिना पर पांच प्रतिशत शुल्क लगता है।

सीपी कोक एक प्रमुख कच्चा माल है। एल्युमीनियम निर्माण लागत में इसका योगदान छह से आठ प्रतिशत रहता है। आयात रोकने के लिए 14 दिसंबर, 2017 को सीपी कोक पर आयात शुल्क 2.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया था जिसका उपयोग ईंधन के उद्देश्य से किया जा रहा था। इसके परिणामस्वरूप गैर-ईंधन दर्जे वाले पेट्रोलियम कोक का सीमा शुल्क बढ़ गया। एल्युमीनियम उद्योग सीपी कोक (गैर-ईंधन दर्जे वाले) का उपयोग करता है जिसमें अधिकतम 3.5 प्रतिशत गंधक होती है। यह भारत में बहुत कम उपलब्ध है और घरेलू आवश्यकता पूरी नहीं कर सकता है। इस वजह से देश सीपी कोक का शुद्ध आयातक बन गया है। इस आयात में एल्युमीनियम की प्रमुख हिस्सेदारी रहती है। एल्युमिना निर्माण लागत में एक अन्य प्रमुख कच्चे माल – कास्टिक सोडा लाई की हिस्सेदारी 20 प्रतिशत रहती है। भारत कास्टिक सोडा का शुद्ध आयातक है और 60 प्रतिशत से अधिक आयात का उपभोग एल्युमीनियम उद्योग द्वारा किया जाता है।

एएआई द्वारा वित्त मंत्रालय को लिखे पत्र में कहा गया है कि भारतीय एल्युमीनियम उद्योग चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा है और बढ़ते आयात, घरेलू बाजार में घटती हिस्सेदारी, उत्पादन और लॉजिस्टिक की बढ़ती लागत की वजह से काफी खतरे में है। इसके अलावा उद्योग के लिए कोयले की कमी और ऊर्जा लागत के कारण मौजूदा अनिश्चित स्थिति ने भारतीय एल्युमीनियम उद्योग की स्थिरता पर प्रतिकूल असर डाला है।

प्रमुख सामग्री की बढ़ती लागत, कच्चे माल के आयात पर उलट शुल्क संरचना, कोयले के उपकर में बढ़ोतरी, अक्षय ऊर्जा खरीद की बाध्यता (आरपीओ), बिजली दर और लॉजिस्टिक लागत के कारण पिछले तीन से पांच सालों के दौरान एल्युमीनियम विनिर्माताओं की उत्पादन लागत 30 प्रतिशत तक बढ़ चुकी है।

घरेलू एल्युमीनियम कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लंदन मेटल एक्सचेंज (एलएमई) पर दामों में गिरावट और आयात में लगातार इजाफे जैसी प्रतिकूल स्थिति का सामना करना पड़ता है। मई 2018 से अक्टूबर 2019 के बीच एलएमई पर एल्युमीनियम के दाम 2,290 डॉलर प्रति टन से 25 प्रतिशत तक गिराकर 1,719 डॉलर हो गए हैं जिससे प्राप्तियों में कमी आई है। इसके अलावा अमेरिका-चीन के बीच बढ़ते व्यापारिक तनाव के कारण भी भारतीय एल्युमीनिमय उद्योग को आयात से भारी खतरा है।

अंतरराष्ट्रीय और घरेलू भाव

As on Dec 16	International Price	International %Chg#	Domestic Price	Domestic %Chg#
METALS ($/tonne)				
Aluminium	1,763.5	-0.4	1,901.1	-3.5
Copper	6,154.0	4.7	6,421.6	2.6
Nickel	14,145.0	-18.2	14,645.8	-18.4
Lead	1,934.0	-8.1	2,211.0	7.0
Tin	17,200.0	2.7	17,955.2	-1.1
Zinc	2,279.0	-4.6	2,591.2	-1.8
Gold ($/ounce)	1,476.5*	-1.5	1,659.3	1.1
Silver ($/ounce)	17.0*	-4.6	19.3	-3.3
ENERGY				
Crude Oil ($/bbl)	67.1*	-1.9	64.4	-1.0
Natural Gas ($/mmBtu)	2.3*	-14.2	2.3	-13.5
AGRI COMMODITIES ($/tonne)				
Wheat	189.8	13.1	301.8	5.8
Maize	185.3*	2.8	330.0	12.8
Sugar	357.0*	11.1	485.7	-0.3
Palm oil	707.5	32.9	1,126.6	30.1
Rubber	1,602.6*	4.5	1,865.9	-1.8
Coffee Robusta	1,409.0*	7.5	1,894.1	-7.7
Cotton	1,484.4	9.3	1,594.6	-2.6

* As on Dec 16, 19 1800 hrs IST, # Change Over 3 Months, Conversion rate 1 USD = 71.0& 1 Ounce = 31.1032316 grams.

Notes:
1) International metals, Indian basket crude, Malaysia Palm oil, Wheat LIFFE and Coffee Karnataka robusta pertains to previous days price. 2) International metal are LME Spot prices and domestic metal are Mumbai local spot prices except for Steel. 3) International Crude oil is Brent crude and Domestic Crude oil is Indian basket. 4) International Natural gas is Nymex near month future & domestic natural gas is MCX near month futures. 5) International Wheat, White sugar & Coffee Robusta are LIFF E future prices of near month contract. 6) International Maize is MATIF near month future, Rubber is Tokyo-TOCOM near month future and Palm oil is Malaysia FOB spot price. 7) Domestic Wheat & Maize are NCDEX future prices of near month contract, Palm oil & Rubber are NCDEX spot prices. 8) Domestic Coffee is Karnataka robusta and Sugar is M30 Mumbai local spot price. 9) International cotton is Cotton no.2-NYBOT near month future & domestic cotton is MCX Future prices near month tures.

Bloomberg chartMaker
Compiled by BS Research Bureau

एमसीएक्स

Name	Tovr (₹ Cr)	OI(000)
Agri commodity		
Cotton	32.7	12435
Oil and Oilseeds	202.1	80011
Spices	0.4	15
Metal(Dec 13)		
Metal- non ferrous	7680.4	60598
Metal- precious	11622.7	463
Oil and gas(Dec 13)		
Gas	2665.7	44156
Oil	15353.8	2818

एनसीडीईएक्स

Name	Tovr (₹ Cr)	OI(000)
Agri commodity		
Cotton	148.3	113370
Grains	219.0	103730
Oil and Oilseeds	790.5	507635
Others	120.5	67490
Pulses	75.0	54280
Spices	71.9	32789

एमसीएक्स बढ़ा/घटा

Name (Maturity)	Close	Day*
Gainers (* % Change)		
Cardamom (Jan 15)	3149.0	3.6
Nickel (Dec 31)	1032.6	1.2
Crude Oil Mumbai (Dec 18)	4242.0	1.0
Crude Oil (Dec 18)	4241.0	1.0
Kapas (Apr 30)	1103.0	0.9
Mentha Oil (Dec 31)	1316.0	0.7
Losers (* % Change)		
Lead (Dec 31)	152.3	-0.6
Zinc (Dec 31)	181.6	-0.6
Zinc Mini (Dec 31)	181.6	-0.5
Lead Mini (Dec 31)	152.4	-0.5
Copper (Dec 31)	440.0	-0.4
Aluminium Mini (Dec 31)	132.9	-0.4

एनसीडीईएक्स बढ़ा/घटा

Name (Maturity)	Close	Day*
Gainers (* % Change)		
Moong-Mertacity (Dec 20)	6882.0	2.9
Guar Seed 10 (Dec 20)	3994.0	1.9
GuarGum 5T-Jodhpur (Dec 20)	7212.0	1.4
Shankar Kapas-Rajkot (Apr 30)	1104.5	1.1
Mustard Seed Rape Oil (Dec 20)	4504.0	1.0
CastorSeed New-Disa (Dec 20)	4244.0	0.3
Jeera Unjha (Jan 20)	15850.0	0.2
Soyabean Indore (Dec 20)	4208.0	0.1
Ref Soy Oil-IDR-2016 (Dec 20)	868.2	0.1
Losers (* % Change)		
Turmeric Nizamabad (Dec 20)	6120.0	-1.0
Maize Kharif (Dec 20)	2030.0	-0.4
Coriander-Kota (Dec 20)	6981.0	-0.4

एमसीएक्स बढ़त/छूट

Name (Maturity)	Futures	Prem/Dis
Premium over spot price (In %)		
Cotton-Rajkot (Dec 31)	19250.0	2.9
Cardamom Vandanmedu (Jan 15)	3149.0	2.8
Kapas Surendranagar (Feb 28)	1043.0	2.4
Gold Petal-Mumbai (Dec 31)	3848.0	1.2
Nickel Mumbai (Dec 31)	1032.6	0.2
Silver Micro-Ahemd (Feb 28)	44153.0	0.1
Discount over spot price (In %)		
Menthol Oil Chandaus (Dec 31)	1316.0	-7.0
Alumini-Mumbai (Dec 31)	132.9	-4.6
Aluminium Mum (Dec 31)	133.0	-4.5
Copper Mum (Dec 31)	440.0	-3.0
Lead Mum (Dec 31)	152.3	-0.7
Lead Min Mumbai (Dec 31)	152.4	-0.6

एनसीडीईएक्स बढ़त/छूट

Name (Maturity)	Futures	Prem/Dis
Premium over spot price (In %)		
Turmeric Nizamabad (Dec 20)	6120.0	1.5
Moong-Merta City (Dec 20)	6882.0	0.9
Crude Palm Oil Kandl (Dec 31)	742.8	0.7
29 mm Cotton-Rajkot (Dec 20)	18740.0	0.4
Paddy-Basmati-Karnal (Dec 20)	3204.0	0.1
Discount over spot price (In %)		
Jeera Unjha (Jan 20)	15850.0	-3.1
Maize-Sangli (Dec 20)	2030.0	-1.5
Soy Bean Indore (Dec 20)	4208.0	-1.5
Guar Gum 5 MT-Jodhpu (Dec 20)	7212.0	-0.8
Coriander-Kota (Dec 20)	6981.0	-0.3
Barley Jaipur (Dec 20)	2125.5	-0.1

कल का हाजिर भाव

औद्योगिक

Metals	Mumbai
Aluminium utensil scrap /kg	98(98)
Aluminium ingots /kg	135(135)
Brass sheet cutting /kg	319(319)
Brass utensil scraps/kg	303(301)
Copper heavy scrap /kg	422(424)
Copper utensil scraps/kg	398(400)
Copper wire bar /kg	456(458)
Lead ingots /kg	157(157)
Nickel Cathodes /kg	1040(1040)
Tin slabs /kg	1275(1275)
Zinc slabs /kg	184(184)

Source:Bombay Metal Exchange

Cotton	Mumbai
Bengal Deshi /Qtl	10742(10742)
DCH - 32 /Qtl	11473(11473)
Jaydhar /Qtl	10067(10067)
Shankar- 6 /Qtl	11276(11276)

Source:Cotton Association of India

Oil	Mumbai
Castor FSG /10kg	910(902)
Castor Comm /10kg	900(892)
Ricebran oil/10kg	760(760)
Groundnut oil /10kg	1065(1060)
Linseed oil /10kg	875(875)
Karanji /10kg	780(780)
Palm oil /10kg	806(812)
Sunflower exp ref /10kg	865(860)
Sunflower oil exp /10kg	815(815)
Soyabean ref / 10kg	860(855)

Source:Bombay Commodity Exchange

सॉफ्ट

Sugar	Mumbai
Mumbai M-30 /Qtl	3302-3596 (3270-3590)

Source:Bombay Sugar Merchants Association

ऊर्जा

Crude Brent-$/Barrel	
NYSE Crude	60.06(60.07)
Brent Crude (UK)	67.09 (66.9)
Brent Crude (WTI)	60.07(60.07)
NYSE Natural Gas-$/Mmbtu	2.3 (2.3)
Furnace/ 180 Cst &/bbl	265.08 (262.56)
Naptha spot /Rs/MT	45170(45170)
LSHS spot/ M.T.	36150(36150)
Furnace Oil spot/ K.L.	33950(33950)

Source:Petroleum Bazaar.com

सर्राफा

Gold	Mumbai
Standard (99.50 Purity) /10 gms	37882(37676)
Pure (99.90 Purity) /10 gms	38034(37827)
Silver.999/ kg	44165(43880)

Source:India Bullion & Jewellers Association

@SPOT PRICE(MCX, NCDEX & ICEX)

Commodity	Unit	PClose	Price (₹.) Close
29 mm Cotton-Rajkot (N)	1 B	18716.25	18672.45
Alumini-Mumbai (M)	1 K	138.15	139.25
Bajra-Delhi (N)	1 Q	1975.00	2010.00
Barley Jaipur (N)	1 Q	2122.75	2127.50
Brass-Jamnagar (M)	1 K	315.90	312.50
Cardamom-Vand. (I)	1 K	2983.00	3067.00
Castor Seed Disa (N)	1 Q	4290.00	4324.40
Castor Seed-Kadi (N)	X	4247.50	4247.50
Chana Bikaner (N)	1 Q	4287.10	4300.00
Chana Delhi (N)	1 Q	4468.80	4504.15
Chana-Akola (N)	X	4450.00	4300.00
Coriander-Gondal (N)	X	6700.00	6650.00
Coriander-Jaipur (N)	X	6900.00	6942.20
Coriander-Kota (N)	1 Q	7016.30	7000.00
Cotton Seed Oilck Ak (N)	1 Q	2118.85	2096.20
Cotton Seed Oilck Ka (N)	1 Q	2068.00	2061.30
Cotton-Kadi (N)	1 B	18644.55	18628.60
CPO-Kandla (M)	10 K	725.90	731.40
Crude Palm Oil Kandl (N)	10 K	740.75	737.95
Diamond 0.3 - Surat (I)	1 CT	875.60	880.10
Diamond 0.5-Surat (I)	1 CT	1526.90	1528.55
Diamond 1-Surat (I)	1 CT	3428.95	3433.75
Gold Ahm (M)	10 G	37691.00	37891.00
Gold Guinea-Ahmedaba (M)	8 G	30274.00	30435.00
Gold Petal-Mumbai (M)	1 G	3778.00	3803.00
Guar Gum 5 MT-Jodhpu (N)	X	7283.35	7269.05
Guar Seed 10 MT-Jodh (N)	1 Q	3937.25	3931.15
Guarseed-Jodhpur (I)	1 Q	3850.00	3825.00
Gur Muzaffar Nagar (N)	40 K	1160.80	1164.35
Isabgulseed-Unjha (I)	1 K	94.10	94.10
Jeera Jodhpur-Jodhpu (N)	X	17000.00	16850.00
Jeera Unjha (N)	1 Q	16408.70	16354.55
Kapas Kadi-Kadi (N)	X	1027.30	1026.35
Kapas-Rajkot (N)	X	1024.55	1023.30
Lead Mum (M)	1 K	155.35	153.30
Maize Kharif-Nizamab (N)	X	2025.00	2043.15
Maize Rabi-Gulabbagh (N)	1	2340.00	2331.60
Maize-Erode (N)	X	2090.90	2088.00
Maize-Feed/Ind-Delhi (N)	1 Q	2200.00	2225.00
Maize-Sangli (N)	X	2051.15	2061.35
Moong-Merta City (N)	1 Q	6674.40	6820.00
Mustardseed Alwar (N)	20 K	4694.50	4746.00
Nickel Mumbai (M)	1 K	1030.30	1030.80
Paddy-Basmati-Karnal (I)	1 Q	3195.00	3195.00
Paddy-Basmati-Karnal (N)	X	3200.00	3200.00
Pepper-Ernakulam (I)	1 K	355.60	354.40
Pepper-Kochi (N)	1 Q	35566.65	35500.00
Rape mustards-Patan (I)	20 K	811.00	822.00
Rapeseed Must.Seed (N)	X	2046.95	2040.00
RBD Palm Olein Kakin (N)	10 K	800.00	800.00
Ref Soya Oil Indore (N)	10 K	863.50	865.10
Ref Soya Oil Mum (N)	10 K	855.05	861.70
Ref Soya Oil Nagpur (N)	10 K	877.50	876.00
Rubber-Kochi (N)	1 Q	13200.00	13250.00
Rubber-Kochi/Ernak. (I)	1 Q	13250.00	13258.00
Silver M-Ahemdabad (M)	1 K	43884.00	44128.00
Soy Bean Indore (N)	1 Q	4252.00	4270.00
Soy Bean Kota (N)	1 Q	4177.00	4191.50
Soy Bean Nagpur (N)	1 Q	4343.00	4292.50
Soy Bean-Akola (N)	X	4297.00	4293.00
Soymeal Indore (N)	1 T	34450.00	34538.00
Soyoil-Indore (I)	10 K	862.00	860.50
Steel Long-Ghaziabad (I)	1 T	27800.00	27910.00
Steel Long-MGG (I)	1 T	28600.00	28900.00
Steel Long-Raipur (I)	1 T	25740.00	25820.00
Sugar M Delhi (N)	1 Q	3245.00	3245.00
Sugar M Grade-Kanpur (N)	1 Q	3333.35	3304.60
Sugar M Grade-Kolhap (N)	1 Q	3295.00	3293.75
Sugar M Kolkatta (N)	1 Q	3435.70	3438.10
Sugar M Muzaff (N)	1 Q	3250.00	3250.00
Sugar S-Kolhapur (N)	1 Q	3133.50	3133.50
Turmeric Nizamabad (N)	1 Q	6016.65	6030.00
Wheat Delhi (N)	1 Q	2250.00	2259.15
Wheat Kota (N)	1 Q	2140.15	2135.00
Wheat New Indore (N)	1 Q	2200.00	2225.00
Wheat New Kanpur (N)	1 Q	2080.00	2075.00
Wheat New-Rajkot (N)	1 Q	2190.00	2180.00
Yellow Peas Mum (N)	1 Q	4850.00	4850.00
Zinc Mumbai (M)	1 K	183.00	182.45

* as on Dec 13, 19

(M) MCX ,(N) NCDEX & (I) ICEX Spot prices

जिंस वायदा

Name Exchange (Units)

DAY SESSION

दिवस सत्र (सोमवार)

कृषि जिंस

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Cotton				
Cotton MCX(1 B)				
Dec 31	19260, 19260, 19150, 19250	1518	278	7300
Jan 31	19390, 19470, 19350, 19450	1224	217	4141
Feb 28	19590, 19600, 19590, 19600	26	6	344
CottonSeed Oil-Akola NCDEX(1 Q)				
Dec 20	2029, 2064, 2027, 2054	7190	413	17900
Jan 20	2051, 2075, 2028, 2072	44030	2688	59830
Feb 20	2062, 2096, 2050, 2093	6760	595	28390
Mar 20	2075, 2114, 2075, 2109	1030	92	2850
Apr 20	2162, 2162, 2100, 2117	190	18	120
Kapas MCX(20 K)				
Apr 30	1094, 1104, 1092, 1103	236	50	616
Shankar Kapas-Rajkot NCDEX(20 Kg)				
Apr 30	1093, 1105, 1091, 1104.5	1217	727	4280
Grains				
Guar Seed 10 NCDEX(1 Qtl)				
Dec 20	3906, 4002, 3888, 3994	6760	436	5990
Jan 20	3954, 4056, 3942, 4042	43555	4599	85585
Feb 20	3994, 4092, 3984, 4078	4405	615	5645
Maize Kharif NCDEX(1 Qtl)				
Dec 20	2030, 2030, 2030, 2030	100	1	4600
Oil and Oilseeds				
CastorSeed New-Disa NCDEX(1 Qtl)				
Dec 20	4248, 4260, 4220, 4244	7270	322	13525
Jan 20	4274, 4300, 4250, 4280	8155	659	29545
Feb 20	4256, 4298, 4256, 4282	290	54	4020
Mar 20	4252, 4276, 4252, 4268	220	36	4445
Crude Palm Oil MCX(10 K)				
Dec 31	727.4, 733, 721, 731.5	10990	779	25680
Jan 31	728.5, 734.9, 721.1, 734.3	12840	840	48070
Feb 28	723.8, 734, 720.9, 732.9	940	73	5910
Mentha Oil MCX(1 K)				
Dec 31	1312.1, 1317.9, 1308.6, 1316	136.44	318	273.6
Jan 31	1321, 1326.5, 1321, 1325.1	31.68	72	76.68
Mustard Seed Rape Oil NCDEX(1 Q)				
Dec 20	4461, 4535, 4402, 4504	5160	212	3040
Jan 20	4480, 4570, 4471, 4554	19590	1243	20500
Feb 20	4480, 4488, 4480, 4488	50	5	1250
Apr 20	4383, 4417, 4372, 4402	460	42	2230
Ref Soy Oil-IDR-2016 NCDEX(10 Kg)				
Dec 20	872, 872.2, 865, 868.2	2035	196	8940
Jan 20	871, 877.8, 864, 876.8	29555	3008	46720
Feb 20	865.2, 870.8, 853.4, 869.6	6535	533	25415
Mar 20	853.6, 864.6, 853.6, 864.6	10	2	80
Soyabean Indore NCDEX(1 Q)				
Dec 20	4234, 4234, 4200, 4208	4540	476	14315
Jan 20	4222, 4260, 4186, 4242	47750	5069	179685
Feb 20	4256, 4290, 4214, 4270	10325	1590	115670
Mar 20	4292, 4328, 4250, 4310	2265	363	36085
Apr 20	4324, 4360, 4318, 4340	440	85	2120
Others				
GuarGum 5T-Jodhpur NCDEX(1 Qtl)				
Dec 20	7053, 7267, 7041, 7212	1655	149	1325
Jan 20	7150, 7337, 7113, 7299	12945	1908	61245
Feb 20	7230, 7435, 7220, 7409	2055	270	4810
Mar 20	7325, 7325, 7325, 7325	15	2	110
Pulses				
Chana-Bikaner NCDEX(1 Qtl)				
Dec 20	4387, 4410, 4361, 4379	3300	169	4640
Jan 20	4395, 4409, 4361, 4388	13100	1059	45880
Mar 20	4334, 4360, 4320, 4339	700	66	3140
Moong-Mertacity NCDEX(1 Qtl)				
Dec 20	6882, 6882, 6882, 6882	25	1	-
Spices				
Cardamom MCX(1 K)				
Jan 15	3130, 3161.3, 3130, 3149	0.5	5	12.4
Feb 14	2993.1, 3022.2, 2993.1, 3018	0.7	7	2.1
Mar 13	2884, 2884, 2884, 2884	0.2	2	0.6
Coriander-Kota NCDEX(1 Q)				
Dec 20	7010, 7015, 6914, 6981	2150	163	3700
Jan 20	6515, 6626, 6428, 6564	2200	189	8260
Apr 20	6807, 6935, 6740, 6876	620	59	4230
Jeera Unjha NCDEX(1 Q)				
Jan 20	15820, 15890, 15520, 15850	1314	387	2679
Mar 20	15775, 15775, 15495, 15625	180	57	243
Turmeric Nizamabad NCDEX(1 Q)				
Dec 20	6182, 6182, 6072, 6120	515	44	4045
Mar 20	6200, 6266, 6120, 6166	1320	196	7185
Apr 20	6110, 6150, 6042, 6096	575	110	2405

धातु

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Metal- non ferrous				
Aluminium MCX(1 K)				
Dec 31	132.95, 133.5, 132.85, 133.35	2595	429	7735
Aluminium Mini MCX(1 K)				
Dec 31	132.9, 133.5, 132.9, 133.35	1374	1081	2798
Jan 31	133.6, 134.1, 133.5, 133.9	119	94	763
Copper MCX(1 K)				
Dec 31	441.15, 443, 440.9, 442.45	12332.5	3994	15447.5
Jan 31	443.35, 447.7, 443.3, 447.4	755	261	2182.5
Feb 28	449.4, 449.4, 449.4, 449.4	2.5	1	37.5
Lead MCX(1 K)				
Dec 31	152.1, 152.4, 151.9, 152.3	4360	740	6190
Lead Mini MCX(1 K)				
Dec 31	152.3, 152.45, 152.05, 152.4	1934	1610	2777
Jan 31	151.75, 152.25, 151.75, 152.25	239	189	1109
Nickel MCX(1 K)				
Dec 31	1030, 1030, 1023, 1027.9	8581.5	5051	3040.5
Jan 31	1019.4, 1028, 1011.8, 1022.6	189	125	408

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Zinc MCX(1 K)				
Dec 31	182.05, 182.3, 181.65, 182	14010	2359	16825
Zinc Mini MCX(1 K)				
Dec 31	182, 182.2, 181.6, 181.9	4850	3910	6995
Jan 31	180.15, 180.15, 179.4, 179.85	723	539	7634
Feb 28	180.35, 180.35, 179.5, 179.85	14	5	25
Metal- precious				
Gold MCX(10 G)				
Feb 05	37725, 37943, 37725, 37911	5.98	4987	16.34
Apr 03	37850, 38000, 37815, 37980	0.37	339	3.08
Gold Guinea MCX(8 G)				
Dec 31	30485, 30540, 30467, 30530	0	96	0
Jan 31	30399, 30458, 30381, 30438	0	41	0
Gold Mini MCX(10 G)				
Jan 03	37740, 37930, 37735, 37901	0.64	5448	0.92
Feb 05	37755, 37935, 37755, 37914	0.13	1214	0.25
Mar 05	37747, 37959, 37747, 37939	0.01	60	0.01
Gold Petal MCX(1 Gm)				
Dec 31	3854, 3865, 3845, 3853	0	351	0.01
Jan 31	3829, 3840, 3829, 3837	0	157	0
Silver MCX(1 K)				
Mar 05	44132, 44547, 44108, 44506	287.55	7472	356.55
May 05	44671, 45000, 44671, 44929	1.26	42	6.03
Silver Micro MCX(1 K)				
Feb 28	44250, 44569, 44100, 44528	23.88	16426	29.48
Apr 30	44637, 45026, 44632, 44988	1.22	980	1.76
Silver Mini MCX(1 K)				
Feb 28	44186, 44580, 44134, 44532	81.12	12840	52.64
Apr 30	44642, 45032, 44637, 45014	1.44	277	2.04

तेल एवं गैस

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Gas				
Natural Gas MCX(1 MB)				
Dec 26	161.4, 164, 161.1, 163.5	30685mb	13866	32389mb
Jan 28	163.6, 163.8, 162.5, 163.3	3080mb	1561	12954mb
Feb 25	161, 161.3, 160.3, 160.8	649mb	412	3293mb
Oil				
Crude Oil MCX(1 BL)				
Dec 18	4236, 4272, 4230, 4259	6964bl	36725	3372bl
Jan 17	4236, 4275, 4233, 4263	488bl	3383	636bl
Feb 19	4260, 4274, 4241, 4261	1bl	8	1bl
Crude Oil Mumbai MCX(1 Bl)				
Dec 18	4233, 4272, 4229, 4258	1447bl	60902	724bl

सायं सत्र (शुक्रवार)

कृषि जिंस

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Cotton				
Cotton MCX(1 B)				
Dec 31	19280, 19300, 19110, 19180	4571	777	7423
Jan 31	19430, 19460, 19280, 19370	2526	431	3835
Feb 28	19510, 19560, 19410, 19450	51	10	336
Kapas MCX(20 K)				
Apr 30	1095.5, 1096.5, 1092, 1094	260	54	608
Shankar Kapas-Rajkot NCDEX(20 Kg)				
Apr 30	1096, 1097.5, 1091.5, 1094.5	1478	678	4166
Oil and Oilseeds				
Crude Palm Oil MCX(10 K)				
Dec 31	736, 737, 719.4, 723.3	23760	1541	26660
Jan 31	739.8, 739.8, 722.1, 725.8	19510	1277	45800
Feb 28	734.3, 736.5, 722.4, 724.3	4260	251	5440
Ref Soy Oil-IDR-2016 NCDEX(10 Kg)				
Dec 20	864.4, 872.4, 859, 864.6	7280	648	9700
Jan 20	865.8, 874.6, 859, 865.8	37530	3674	45135
Feb 20	867, 870, 853.2, 859.8	6400	618	22420
Mar 20	865, 865, 852, 863	75	9	80

धातु

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Metal- non ferrous				
Aluminium MCX(1 K)				
Dec 31	133.75, 134.25, 132.7, 132.95	11050	1580	7140
Aluminium Mini MCX(1 K)				
Dec 31	133.65, 134.15, 132.6, 132.9	3983	3158	2579
Jan 31	134, 134.45, 133.35, 133.55	227	213	744
Copper MCX(1 K)				
Dec 31	442.8, 445.4, 438.75, 440	57762.5	18237	12350
Jan 31	448.25, 449.9, 443.8, 445.05	2352.5	903	1760
Lead MCX(1 K)				
Dec 31	153.4, 153.95, 152.1, 152.25	20725	3375	4855
Lead Mini MCX(1 K)				
Dec 31	153.4, 153.9, 152.15, 152.4	7814	6318	2132
Jan 31	152.75, 153.15, 151.8, 152	520	452	992
Nickel MCX(1 K)				
Dec 31	1020.7, 1035.5, 1020.7, 1032.6	24786	14958	1497
Jan 31	1017.4, 1029.9, 1016.7, 1028.2	591	381	381
Feb 28	1023, 1023, 1023, 1023	1.5	1	1.5
Zinc MCX(1 K)				
Dec 31	183.1, 184.5, 181.35, 181.6	70310	11172	12805
Zinc Mini MCX(1 K)				
Dec 31	182.85, 184.2, 181.3, 181.55	22144	16784	5821
Jan 31	180.6, 181.9, 179.3, 179.55	3753	2237	7492
Feb 28	180.25, 180.25, 180.25, 180.25	1	1	13
Metal- precious				
Gold MCX(10 G)				
Feb 05	37466, 37840, 37466, 37773	16.52	14138	15.36
Apr 03	37619, 37860, 37530, 37806	0.52	465	2.86
Gold Guinea MCX(8 G)				
Dec 31	30416, 30550, 30408, 30508	0	347	0
Jan 31	30356, 30425, 30101, 30385	0	122	0
Gold Mini MCX(10 G)				
Jan 03	37512, 37810, 37400, 37776	2.19	18208	0.78
Feb 05	37501, 37832, 37475, 37783	0.47	3783	0.23
Mar 05	37561, 37840, 37522, 37784	0.01	97	0.01
Gold Petal MCX(1 Gm)				
Dec 31	3846, 3852, 3826, 3848	0.01	2019	0.01
Jan 31	3828, 3834, 3816, 3832	0	499	0
Feb 28	3820, 3838, 3818, 3831	0	12	0
Silver MCX(1 K)				
Mar 05	43908, 44370, 43880, 44126	672.03	18535	356.28
May 05	44610, 44752, 44400, 44525	1.89	63	6.27
Silver Micro MCX(1 K)				
Feb 28	43970, 44390, 43907, 44153	61.47	42945	29.55
Apr 30	44442, 44900, 44419, 44638	3.81	2614	1.64
Aug 31	44630, 46991, 44630, 45811	0	2	0.01
Silver Mini MCX(1 K)				
Feb 28	43855, 44389, 43710, 44151	209.14	32144	47.94
Apr 30	44443, 44860, 44437, 44643	2.54	459	1.87

तेल एवं गैस

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Gas				
Natural Gas MCX(1 MB)				
Dec 26	164.1, 165.1, 159.8, 162.8	150136mb	64488	28598mb
Jan 28	164.8, 165.3, 160.1, 162.6	12956mb	6664	12451mb
Feb 25	162.7, 163.1, 158.2, 160.1	1265mb	931	3108mb
Oil				
Crude Oil MCX(1 BL)				
Dec 18	4196, 4273, 4194, 4241	28531bl	137831	1918bl
Jan 17	4200, 4273, 4194, 4244	1594bl	9448	483bl
Feb 19	4219, 4250, 4219, 4233	1bl	6	1bl
Crude Oil Mumbai MCX(1 Bl)				
Dec 18	4198, 4272, 4192, 4242	6212bl	231048	416bl

g-grams, k-kilograms, q-quintals, t-tonnes, b-bales,bl-barels,mb-mmBTU,m-Mnd; Quantity & Open interest in tonnes except for crude oil and natural gas; For Gas is '000 mmBTU & for crudeoil in '000 barrel; Market price in ₹.

नई दिल्ली | 17 दिसंबर 2019 मंगलवार बिज़नेस स्टैंडर्ड

सोशल मीडिया कंपनियां हुई मुस्तैद

करन चौधरी और नेहा अलावधी

फेसबुक, ट्विटर, टिकटोक, हेलो, शेयरचैट तथा दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के कुल 15,000 से अधिक मध्यस्थ अपने प्लेटफार्मों पर किसी भी प्रकार के फर्जी, भड़काऊ या सांप्रदायिक खबरों के प्रसार को रोकने के लिए पिछले 10 दिनों से अतिरिक्त समय में भी काम कर रहे हैं।

नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोध में देशभर में हो रहे प्रदर्शनों के बीच सोशल मीडिया कंपनियां किसी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहतीं। विभिन्न सोशल मीडिया कंपनियों के सूत्रों ने बताया कि सोशल मीडिया मध्यस्थों को अपने प्लेटफॉर्म पर अधिक समय बिताने के लिए कहा गया है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई सांप्रदायिक अथवा फर्जी खबरें प्रसारित न हों।

एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने कहा, 'रात की शिफ्ट में अधिक लोगों को काम करने के लिए कहा जा रहा है क्योंकि इस समय प्लेटफॉर्म पर अधिक सामग्री डाली और साझा की जाती है। दूसरे कार्यों में लगे मध्यस्थों को सीएए संबंधी सामग्री पर लगाया गया है। फिलहाल सभी के लिए यह वरीयता है।'

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत अधिक सामग्री स्थानीय भाषाओं में साझा की जाती है जिसके चलते स्थानीय भाषा की निगरानी करने वालों को अतिरिक्त सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। स्थानीय भाषा आधरित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े एक मध्यस्थ ने कहा, 'हम मुख्य तौर पर ऐसे राज्यों से आने वाली स्थानीय पोस्ट तथा वीडियो पर ध्यान दे रहे हैं, जहां से विरोध प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं। सोमवार दोपहर तक हमने करीब 2,500 फर्जी खबरें तथा सांप्रदायिक सामग्री को हटाया है।' फिलहाल वह असम में चल रहे विरोध प्रदर्शन से जुड़ी खबरों को देख रहे हैं।

आईटी मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार छोटे शहरों और कस्बों में बढ़ती लोकप्रियता के बीच इन प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग काफी अधिक बढ़ गया है। बहुत से उपयोगकर्ता हाल के समय में ही तकनीक से परिचित हुए हैं और इस कारण ये फर्जी खबरों के प्रसार के लिए अधिक संवेदनशील हैं।

विभिन्न राज्य पुलिस के साथ साथ दिल्ली पुलिस भी सोशल मीडिया पोस्टों पर संवेदनशील या सांप्रदायिक नजरिये वाली खबरों को रोकने के लिए प्रयास कर रही है। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को बताया कि वे एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नजर रख रहे हैं और इन सभी फर्मों के साथ संपर्क में हैं ताकि इस तरह की खबरों को जल्द से जल्द हटाया जाना सुनिश्चित किया जा सके।

दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, 'हमने इन कंपनियों के अधिकारियों के साथ कई बार बातचीत की है। हमने उनसे अनुरोध किया है कि कानून-व्यवस्था के लिए चुनौती पैदा करने वाली किसी भी तरह की सोशल मीडिया पोस्ट को तुरंत हटाया जाए। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वे सहयोग करेंगे।'

हाल ही में टिकटोक, हेलो, बीगो लाइव समेत दूसरी चीनी सोशल मीडिया कंपनियों को संसद की स्थायी समिति ने बुलाया था जिसमें महिलाओं के खिलाफ साझा की जाने वाली जानकारी को हटाए जाने के प्रयासों को बढ़ाया जा सके।

मामले से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि समिति ने उन सभी उपायों की जानकारी ली, जिनके जरिये ये कंपनियां ऑनलाइन सामग्री की जांच तथा गलत सामग्री रोकने के लिए जरूरी कदम उठा रही हैं। कई सरकारी एजेंसियों तथा अदालतों ने इन चीनी ऐप पर युवा वयस्कों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया है। स्थायी समिति सोशल मीडिया कंपनियों द्वारा उठाए गए इस तरह के सभी कदमों की समीक्षा करना चाहती है।

- विरोध प्रदर्शन से जुड़ी फर्जी खबरें रोकने के प्रयास कर रहीं सोशल मीडिया कंपनियां
- फेसबुक में सामग्री की जांच करने के लिए नियुक्त हैं वैश्विक स्तर पर करीब 30,000 कर्मी
- ट्विटर पर करीब 1,500 लोग करते हैं सामग्री की जांच
- भारत में प्रसारित सामग्री की जांच के लिए टिकटोक में हैं 250 से अधिक लोग

कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा इंडिया गेट पर छात्रों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन करते हुए

नागरिकता कानून के विरोध में सड़क पर ममता

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि उनके जिंदा रहते नागरिकता संशोधन कानून राज्य में नहीं होगा लागू

अभिषेक रक्षित

नागरिकता संशोधन कानून को लेकर बढ़ती हिंसा के बीच सोमवार को पश्चिम बंगाल में एक नया राजनीतिक घटनाक्रम शुरू हो गया जब राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वह जब तक जिंदा हैं तब तक संशोधित नागरिकता कानून नहीं लागू करेंगी और केंद्र को उनकी लाश से गुजर कर ही नागरिकता कानून लागू करना होगा। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने उन पर हिंसा फैलाने और हिंसक लोगों के साथ षडयंत्र करने का आरोप लगाया।

लेकिन इस कानून का विरोध कर रही वाम मोर्चा ने भाजपा और ममता दोनों पर आरोप लगाए। नागरिकता संशोधन कानून का विरोध लोकतांत्रिक तरीके से करने के लिए राज्य में सत्तासीन दल तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और वाम मोर्चा ने कई रैलियां आयोजित कीं जबकि भाजपा ने पुलिस की झड़प के बीच इस कानून के समर्थन में दूसरी रैली निकाली। दक्षिणी पश्चिम बंगाल में हिंसक घटनाओं की वजह से रेल सेवा और वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुईं।

मुख्यमंत्री ने कोलकाता में वृहद रैली का आयोजन करते हुए लोगों से नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) का जमकर विरोध करने को कहा और साथ ही यह अपील की कि प्रदर्शनकारी शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध जताएं। हालांकि इससे पहले भी उन्होंने राज्य में शांति व्यवस्था बरकरार रखते हुए लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करने की गुहार लगाई थी लेकिन उसके बावजूद भीड़ ने सड़कों की आवाजाही और रेल यात्रा को बाधित करने की कोशिश की गई। ममता की वृहद रैली की शुरुआत में उनकी पार्टी के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने लोगों को संबोधित किया लेकिन तुरंत ही तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने कमान संभाल ली और भीड़ को बांग्ला और हिंदी में संबोधित किया।

राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता की रैली को 'असंवैधानिक' करार देते हुए उन्हें यह सुझाव दिया कि वह भड़काऊ भाषणों से परहेज करें और राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर ध्यान दें। उन्होंने ममता को व्यक्तिगत रूप से राज्य में हिंसा से उपजे मौजूदा हालात के बारे में अवगत कराने के लिए कहा था। उन्होंने ट्विटर के जरिये अपनी अप्रसन्नता जाहिर करते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण एवं अप्रत्याशित करार दिया। उन्होंने लिखा, 'इस भयावह स्थिति को देखते हुए मैंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सोमवार को अपनी सुविधानुसार व्यक्तिगत रूप से राजभवन आकर स्थिति की जानकारी देने को कहा है। अभी तक मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से कोई जवाब नहीं आया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण और अप्रत्याशित है।'

'खपत बढ़ाने पर होगा जोर'

पृष्ठ 1 का शेष

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह कानून भेदभावपूर्ण और विभाजनकारी है। सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सांसदों और राज्यों के नेताओं से बात कर रहे हैं और उन्हें सरकार के रुख से अवगत करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इन मुद्दों पर पूरा ध्यान दे रही है। देश की अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में है और देश की एकता तथा सौहार्द को कोई खतरा नहीं है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ग्रामीण कार्यक्रमों पर जोर देकर खपत बहाल करने की दिशा में काम कर रही है और यह सुनिश्चित कर रही है कि पैसा उपभोक्ताओं तक पहुंचे। बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में सरकारी निवेश को गंभीरता से लिया जा रहा है और छोटी तथा मझोली कंपनियों के बकाये का भुगतान किया जा रहा है। सरकार ने उनका 61,000 करोड़ रुपये के लंबित बकाये का भुगतान कर दिया है। सीतारमण ने कहा, 'मैं यह सुनिश्चित कर रही हूं कि कोई भी बकाया न रहे और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां अपने बिलों का भुगतान करें।' सितंबर तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर 4.5 फीसदी रही जो छह साल में सबसे कम है। कारखानों से उत्पादन में गिरावट आई है और खपत भी कम हुआ है। लेकिन सीतारमण ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कोई समयसीमा देने से इनकार कर दिया और कहा कि जब तक जरूरी होगा, सरकार अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करती रहेगी।

उन्होंने स्वीकार किया कि इस वित्त वर्ष के पहले आठ महीने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह उम्मीद से कम रहा और जीएसटी दरों को संशोधित करने के बारे में उनके विभाग में कोई चर्चा नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार राजस्व संग्रह में कमी पर राज्यों को क्षतिपूर्ति देने के अपने वादे से पीछे नहीं हटेगी।

पायल रोहतगी की जमानत अर्जी खारिज

कोटा की एक अदालत ने सोशल मीडिया पर नेहरू गांधी परिवार के खिलाफ कथित आपत्तिजनक सामग्री डालने के मामले में अभिनेत्री पायल रोहतगी की जमानत अर्जी खारिज कर दी और उन्हें 24 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।

बूंदी की पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता ने बताया कि रोहतगी को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया था। एक दिन पहले उन्हें अहमदाबाद में उनके घर से हिरासत में लेकर बूंदी लाया गया था। उन्हें रविवार रात को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया था। रोहतगी के वकील भूपेंद्र सहाय सक्सेना ने जमानत अर्जी खारिज हो जाने की पुष्टि की लेकिन यह भी कहा कि वह ऊपरी अदालत जाएंगी। बिगबॉस की पूर्व प्रतिस्पर्धी ने छह सितंबर और 21 सितंबर को विभिन्न सोशल मीडिया साइटों पर मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिया गांधी और इस परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट की थी। प्रदेश युवा कांग्रेस के महासचिव चार्मेश शर्मा ने आपत्तिजनक सामग्री की प्रतियों के साथ शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि आपतिजनक सामग्री से देश की छवि को नुकसान पहुंचती है, उससे अश्लीलता, धार्मिक घृणा फैलती है तथा महिला की छवि खराब होती है। पुलिस ने रोहतगी के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धाराओं 66 और 67 के तहत मामला दर्ज किया था। *भाषा*

सत्ता विरोधी रुझान से भाजपा होगी परेशान ?

राधिका रामशेषन

देश के दो प्रमुख आदिवासी राज्य झारखंड और छत्तीसगढ़ 2000 में क्रमश: बिहार और मध्य प्रदेश के विभाजन के बाद अस्तित्व में आए थे। हालांकि राजनीतिक स्थिरता के मामले में ये दोनों राज्य अलग-अलग खड़े दिखाई देते हैं। छत्तीसगढ़ के गठन के बाद वहां गैर-आदिवासी मुख्यमंत्रियों के नेतृत्व में सभी सरकारों ने अपना कार्यकाल पूरा किया है। झारखंड में ऐसी स्थिति नहीं रही है। राज्य में मौजूदा रघुवर दास के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार को छोड़कर कोई भी सरकार अपना पांच वर्षों का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई।

रघुवर दास सरकार 2014 में भाजपा की सहयोगी ऑल झारखंड स्टुडेंट्स यूनियन (आजसू) और झारखंड विकास मोर्चा (प्रजातांत्रिक) या जेवीएम (पी) से आए विधायकों की मदद से बनी थी। इस बार भाजपा मौजूदा चुनाव आजसू के बिना अकेले ही लड़ रही है। ऐसे में यह सवाल भी उठ रहा है कि भाजपा ने आजसू को छोड़कर जोखिम लिया है या एक सोची-समझी रणनीति के तहत यह कदम उठाया है? पटना के एक वरिष्ठ चुनाव विश्लेषक अभय कुमार कहते हैं,'राज्य विधानसभा के चुनाव में भाजपा को शिकस्त मिलती है तो इसके लिए सरकार और मुख्यमंत्री दास के खिलाफ जनता का नकारात्मक रुख मुख्य कारण होगा। आजसू किसी भी तरह इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगी क्योंकि राज्य के कुछ हिस्सों में ही इसकी स्थिति मजबूत है।' 2014 के चुनाव में 81 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा 72 सीटों पर लड़ी थी और 31.26 प्रतिशत मत के साथ 37 सीटें लाने में सफल रही थी। आजसू आठ सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 3.68 प्रतिशत मत के साथ पांच सीटों पर विजयी रही थी।

हालांकि झारखंड के राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर आजसू ने बिना उठापटक के भाजपा से अपनी राह जुदा की है तो इसकी कुछ अपनी वजह है। रांची के एक राजनीतिक विश्लेषक ने कहा, 'आजसू को शर्तिया तौर पर लगने लगा था कि भाजपा के साथ गठबंधन जारी रखने से उसका अपना जनाधार खिसक जाएगा। महतो (कुर्मी) पिछड़ी जाति पर आजसू की लगभग पूरी पकड़ थी और इसकी वजह यह थी कि राम टहल चौधरी के अलावा लंबे समय तक भाजपा के पास कोई विश्वसनीय कुर्मी नेता नहीं था।' चौधरी रांची से 1991 से 2004 तक सांसद थे और 2019 में टिकट नहीं मिलने के बाद उन्होंने भाजपा से संबंध विच्छेद कर लिया था। इस विश्लेषक ने कहा,' भाजपा एक कुर्मी नेता लाने के लिए इतनी हड़बड़ी दिखा रही थी कि इसने शैलेंद्र महतो को भी अपने पाले में करने की कोशिश की, लेकिन इसमें सफल नहीं रही।' महतो अपने राजनीतिक करियर के अंतिम पड़ाव पर भाजपा और कांग्रेस के बीच डोलते रहे और और अब राजनीति से लगभग सन्यास लेने की स्थिति में पहुंच गए हैं।

ऐसी खबरें थीं कि झारखंड भाजपा में दास के सबसे बड़े नेता के रूप में उभरने से आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो की नींद उड़ गई थी। महतो को लगने लगा कि देर-सबेर दास महतो का कुर्मी वोट बैंक हथिया लेंगे और राज्य की राजनीति में आजसू का पत्ता काट देंगे। दास झारखंड में पिछड़ी जाति से ताल्लुक रखने वाले पहले मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने राज्य में कुर्मी सहित पिछड़ी जातियों को एकजुट करने की रणनीति पर काम शुरू किया था। आजसू के प्रवक्ता देवशरण भगत ने दास की मंशा की पुष्टि भी कर दी। भगत ने कहा, 'भाजपा राज्य में जातीय समीकरण पूरी तहर अपने पक्ष में करना चाहती थी, लेकिन हमें यह स्वीकार नहीं था और इस वजह से भाजपा का साथ छोड़ना पड़ा। अगर हमने अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव नहीं लड़ा होता तो हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट जाता। अकेले लड़ने से हमें अपनी विचारधारा लोगों तक पहुंचाने में मदद मिली। हम दिल्ली और रांची को झारखंड के गांवों पर हावी होने नहीं दे सकते। इस बार ग्रामीण मतदाता आजसू के माध्यम से अपनी मंशा जता देंगे।'

इसके उलट रांची में भाजपा के एक सूत्र ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने नेताओं को अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार किया। उन्होंने कहा, 'इसके पीछे तर्क यह है कि जितनी अधिक सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे हमारे जीतने की संभावनाएं उतनी बढ़ेंगी और इससे कुल सीटों में भी इजाफा हो सकेगा।' हालांकि सूत्र ने यह स्वीकार किया कि दास के खिलाफ सत्ता विरोधी रुझान की आशंका और उनके बारे में आदिवासी समुदाय के खिलाफ होने की धारणा हमें नुकसान पहुंचा सकती है। उन्होंने कहा,'अगर हम 2014 का मत प्रतिशत बरकरार रख पाते हैं तो यह हमारे लिए बड़ी बात होगी। पिछली बार हमने आजसू के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, जबकि कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अलग-अलग चुनावी समर में उतरी थी। इस बार कांग्रेस, झामुमो और राजद एक साथ आ गए हैं। ज्यादातर सीटों पर सीधी टक्कर है। हमारी नजरें उन सीटों पर हैं, जहां मुकाबला बहु-कोणीय है।' जेवीएम (पी) की स्थापना बाबूलाल मरांडी ने भाजपा से निकलने के बाद की थी और यह भी भाजपा की तरह अकेले चुनाव लड़ रही है।

आखिर 2014 के आंकड़े क्या इशारे कर रहे हैं? पहली बात तो यह कि कई सीटों पर सीधी लड़ाई नहीं होने के बाद भी भाजपा के लिए चुनौती कम नहीं है। चुनाव विश्लेषक अभय कुमार द्वारा किए अध्ययन के अनुसार 18 सीटों में सात पर भाजपा 1,000 से 5,000 मतों के अंतर से चुनाव जीती थी और आजसू एक जबकि झामुमो और कांग्रेस को तीन-तीन सीटें मिली थीं। 19 सीटों पर भाजपा 1 लाख से 3 लाख के विशाल अंतर से विजयी रही थी। दूसरी बात यह कि भाजपा ग्रामीण क्षेत्रों में कम अंतर से और शहरी क्षेत्रों में बड़े अंतर से विजयी रही थी। तोरपा सीट पर भाजपा 43 वोट से झामुमो से हार गई थी, वहीं बोरियो सीट इसने 712 वोट से जीती थी। रांची में पार्टी 58,863 के बड़े अंतर से जीती थी तो बोकारो में इसकी जीत का अंतर 72,643 रहा था।

झारखंड में मौजूदा भाजपा सरकार को छोड़कर कोई भी सरकार अपना पांच वर्षों का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई *(फाइल फोटो)*